▪ RNI No. 58061/93 ▪ वर्ष - 21 ▪ अंक - 298 ▪ पृष्ठ - 8 ▪ रु. 5/- बेंगलूरु » शुक्रवार » 29-05-2026 ▪ www.dakshinbharat.com ▪ Email : news@dakshinbharat.com

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರಮತ | ಹಿಂದಿ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ | बेंगलूरु और चेन्नई से एक साथ प्रकाशित

5 सावरकर के आदर्शों से भारत महान और बिहार समृद्ध बनेगा : सम्राट चौधरी

6 अब बक्शे नहीं जाएंगे घुसपैठिए

7 मुकेश अंबानी ने लगातार छठे साल नहीं लिया कोई वेतन

बेंगलूरु में गुरुवार को ईद-उल-अज़हा के अवसर पर मैसूर रोड ईदगाह मैदान में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विशेष नमाज अदा की और अमन, भाईचारे तथा खुशहाली की दुआ मांगी।

फर्स्ट टेक

यूक्रेन ने अमेरिका से मांगी है और पैट्रियट मिसाइल

कीव/एपी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह उनके देश को रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों का मुकाबला करने में सक्षम पैट्रियट वायु रक्षा मिसाइल मुहैया कराने का अमेरिका से लगातार आग्रह कर रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने इस सप्ताह की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कांग्रेस (अमेरिकी संसद) को अमेरिका निर्मित गोला-बारूद की अधिक आपूर्ति के लिए पत्र भेजा था, जिसका उन्हें अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। उन्होंने आगाह किया कि ईरान युद्ध के कारण अमेरिकी युद्धक सामग्री कम होने से यूक्रेन को आपूर्ति खतरनाक रूप से कम हो रही है। स्वीडन दौरे के दौरान पत्रकारों से बातचीत में जेलेंस्की ने कहा, ''मेरा मानना है कि अमेरिका को जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। हम लगातार आग्रह कर रहे हैं।''

तुर्किये के काला सागर तट पर ड्रोन से तीन तेल टैंकर पर हमला

इस्तांबुल/एपी। तुर्किए के काला सागर तट पर बृहस्पतिवार को तीन तेल टैंकर पर ड्रोन से हमला किया गया। एक शिपिंग एजेंसी ने यह जानकारी दी। ये सभी जहाज़ पश्चिमी प्रतिबंध सूची में 'शैडो फ्लीट' के हिस्से के रूप में शामिल हैं, जो रूस के तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात करते हैं और यूक्रेन युद्ध के कारण मॉस्को पर लगे पश्चिमी प्रतिबंधों से बचते हैं। इनमें से एक जहाज़ को मार्च में भी निशाना बनाया गया था। 'ट्रिबेका शिपिंग' ने बताया कि पलाऊ ध्वज वाला जहाज जेम्स द्वितीय सिनोप के तुर्केली जिले से 80 किलोमीटर उत्तर में जा रहा था तभी उस पर हमला हुआ।

29-05-2026 सूर्यास्त 6:41 बजे | 30-05-2026 सूर्योदय 5:52 बजे

BSE	NSE
75,867.80	23,907.15
(-141.91)	(-6.55)

सोना	चांदी
16,069 रु.	276,893 रु.
(24 कैरेट) प्रति ग्राम	प्रति किलो

मिशन मंडेला
दक्षिण भारत राष्ट्रमत
दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक
epaper.dakshinbharat.com

कैलाश मण्डेला, मो. 9828233434

फितरत हमारी

कितने ही कानून बना दो,
हम धाराएं तोड़ेंगे।
चाहे भर देंगे जुर्माना,
या ले-दे के छोड़ेंगे।
किनकी जेबें होगी भारी,
किनके बाल झिंझोड़ेंगे।
सिस्टम के नाकारापन पर,
सिर्फ ठीकरा फोड़ेंगे।।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से

सिद्दरामय्या ने दिया इस्तीफा

कांग्रेस आलाकमान के निर्देशानुसार डी के शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु/भाषा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या ने बृहस्पतिवार को यहां लोक भवन में राज्यपाल के विशेष सचिव को अपना इस्तीफा सौंप दिया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत की अनुपस्थिति में विशेष सचिव प्रभु शंकर ने इस्तीफा ग्रहण किया। लोकभवन के सूत्रों के अनुसार गहलोत व्यक्तिगत कारणों से अपने मूल स्थान इंदौर में हैं।

जब सिद्दरामय्या ने राज्यपाल के विशेष सचिव को अपना इस्तीफा सौंपा तब उनके साथ उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार और अन्य मंत्रिमंडल सहयोगी मौजूद थे। प्रभु शंकर ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, ''मुझे इस्तीफा मिल गया है, लेकिन इसे राज्यपाल स्वीकार करेंगे।''

इस्तीफा सौंपने के बाद सिद्दरामय्या ने कहा, '' मैंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है । चूंकि राज्यपाल थावरचंद गहलोत शहर में नहीं हैं, इसलिए मैंने अपना त्यागपत्र उनके विशेष सचिव को सौंप दिया।'' उन्होंने कहा, ''मैंने बार-बार कहा था कि जब भी आलाकमान मुझे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने को कहेगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा। आलाकमान ने मुझे दो दिन पहले पद छोड़ने का निर्देश दिया था, जिसके अनुसार मैंने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया।''

उन्होंने कहा, ''मुझे पूरा विश्वास है कि राज्यपाल संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लेंगे। मुझे दो बार कर्नाटक के लोगों की सेवा करने का मौका मिला, मैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे को धन्यवाद देता हूं।''

इससे पहले सिद्दरामय्या ने अपने सरकारी निवास पर मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के लिए आयोजित जलपान में मंत्रियों को पद छोड़ने के अपने फैसले से अवगत कराया और यह भी कहा कि कांग्रेस आलाकमान के निर्देशानुसार उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे।

साफ अंतरात्मा से मैंने पद छोड़ा : सिद्दरामय्या

बेंगलूरु/भाषा। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद के लिए उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार के साथ सत्ता संघर्ष और महीनों से चल रही नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों पर पूर्ण विराम लगाते हुए कांग्रेस नेता सिद्दरामय्या ने बृहस्पतिवार को इस पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें राज्यसभा का टिकट देने की पेशकश की है, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया है क्योंकि वह कर्नाटक में सक्रिय राजनीति को प्राथमिकता देते हैं ताकि 'अपनी आखिरी सांस तक सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ सकें।''

महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करेंगे : नायडू

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

अमरावती/भाषा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने बृहस्पतिवार को कहा कि तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) विधानमंडल में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करेगी, भले ही अन्य दलों के बीच राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रावधान पर सहमति नहीं बन पाये।

मंगलागिरि स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित वार्षिक तेदेपा सम्मेलन 'महानडू' के अंतिम दिन नायडू ने कहा कि उन्हें पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और आईटी मंत्री नारा लोकेश द्वारा प्रस्तावित आरक्षण पर कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा, ''यदि सभी राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्तर पर महिला आरक्षण पर सहमत नहीं हो पाते हैं, तो तेदेपा इसे पार्टी के भीतर लागू करेगी और आंध्र प्रदेश विधानमंडल में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगी।''

उन्होंने कहा कि तेदेपा देशभर में महिलाओं के लिए आरक्षण के लिए संघर्ष करेगी।

मुख्यमंत्री ने सभी क्षेत्रों में महिलाओं की ताकत और क्षमताओं का उपयोग करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

नायडू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी महिला आरक्षण को लेकर प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि सभी को इसका समर्थन करना चाहिए और इसके कार्यान्वयन के लिए काम करना चाहिए।

त्विषा मौत मामला:

सीबीआई ने सास एवं पूर्व न्यायाधीश गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया

भोपाल/भाषा। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द किए जाने के एक दिन बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने बृहस्पतिवार को सिंह को उनकी बहू त्विषा शर्मा की मौत के मामले में गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई की एक टीम ने सिंह को हिरासत में लेने से पहले भोपाल के बाग मुगलिया एक्सटेंशन इलाके में उनके आवास पर उनसे पूछताछ की। अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी पूर्व न्यायाधीश को औपचारिक तौर पर हिरासत में लेने के लिए उन्हें शुक्रवार को सक्षम अदालत के समक्ष पेश कर सकती है। सिंह के बेटे और त्विषा के पति समर्थ सिंह पहले से ही केंद्रीय एजेंसी की हिरासत में हैं। समर्थ पेशे से वकील हैं। अधिकारियों के अनुसार, सीबीआई की योजना 33 वर्षीय पूर्व मॉडल-अभिनेता की मौत की परिस्थितियों की जांच के लिए मां-बेटे का आमना-सामना कराना है ताकि उनके बयानों से तथ्य सामने लाया जाए।

आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में 'दोहरा मापदंड' नहीं होना चाहिए : डोभाल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मॉस्को/भाषा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई किये जाने का बृहस्पतिवार को आह्वान करते हुए कहा कि इसका मुकाबला करने में ''दोहरा मापदंड'' नहीं अपनाया जा सकता है। मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास के अनुसार डोभाल ने यहां एक अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए यह बात कही।

डोभाल ने मॉस्को में आयोजित पहले अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मंच और सुरक्षा मामलों के उच्च प्रतिनिधियों की 14वीं बैठक में हिस्सा लिया।

दूतावास ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''इस बैठक की मेजबानी रूसी संघ की सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु ने की।''

इसने कहा, ''एनएसए ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरा मापदंड नहीं अपनाया जा सकता। जिम्मेदार देशों को अपने विकल्पों का मूल्यांकन करना होगा और यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का समर्थन करते हैं या निर्णायक कार्रवाई से उनका मुकाबला करते हैं।''

डोभाल ने ''1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद स्थापित संरचनाओं और संस्थानों में सुधार की तत्काल आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला ताकि वे समकालीन अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा खतरों से निपटने में प्रभावी हो सकें''।

पश्चिम एशिया की स्थिति का जिक्र करते हुए, डोभाल के हवाले से दूतावास ने कहा कि ''होर्मुज जलडमरूमध्य और लाल सागर समेत अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से व्यापार की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना आवश्यक है''।

कुवैत पर हुए मिसाइल हमले

जोखिम में पड़ सकता है युद्धविराम

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

दुबई/एपी। युद्धविराम का उल्लंघन करते हुए कुवैत पर किए गए ताजा मिसाइल हमले को लेकर अमेरिकी सेना ने बृहस्पतिवार को ईरान की आलोचना की। इस हमले ने युद्ध को खत्म करने के लिए जारी वार्ता को जोखिम में डाल दिया है। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा कि कुवैत ने बुधवार देर रात ईरान द्वारा दागी गई मिसाइलों को मार गिराया, और फारस की खाड़ी में अमेरिका के प्रमुख सहयोगियों में से एक पर ईरानी हमले को ''युद्धविराम का घोर उल्लंघन'' बताया।

कुवैत ने पूर्व में, अपने क्षेत्र पर हमले होने की जानकारी दी थी। वहीं, ईरान ने कहा कि उसने खाड़ी क्षेत्र में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर इस सप्ताह की शुरुआत गोलाबारी कर जवाबी कार्रवाई की है।

अमेरिका और ईरान ने पूरे सप्ताह एक-दूसरे पर हमले किए हैं, जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें विश्वास है कि उनका प्रशासन युद्ध समाप्त करने के लिए ईरान के साथ बातचीत में प्रगति कर रहा है।

अमेरिका ने सोमवार को कहा था कि उसने दक्षिणी ईरान में मिसाइल स्थलों और बारूदी सुरंग बिछाने वाली नौकाओं पर ''रक्षात्मक'' हमले किए।

अमेरिकी अधिकारियों ने बुधवार देर रात वाशिंगटन में कहा कि सेना ने ईरान पर और हमले किए।

जल विवादों का समाधान सहयोग के जरिये किया जाए : प्रधानमंत्री मोदी

- मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि बिजली की लागत को कम करने, ऊर्जा सुरक्षा में सुधार करने तथा घरेलू और सामुदायिक स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए छतों पर सोलर पैनल को 'मिशन मोड' में अपनाया जाना चाहिए।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्यों से सहयोग, समय पर मंजूरी और प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी के माध्यम से अंतरराज्यीय जल विवादों का समाधान करने की अपील करते हुए कहा है कि केन-बेतवा परियोजना को एक आदर्श के रूप में काम करना चाहिए।

बुधवार शाम को आयोजित 51वीं 'प्रगति' बैठक की अध्यक्षता करते हुए, प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि सार्वजनिक परियोजनाओं को लागू करने में देरी से न केवल लागत बढ़ती है, बल्कि नागरिकों को जरूरी सुविधाओं और विकास के लाभ भी समय पर नहीं मिल पाते। उन्होंने कहा कि हर देरी का लोगों के जीवन, क्षेत्रीय विकास और सार्वजनिक संसाधनों पर सीधा असर पड़ता है।

बैठक में नौ राज्यों में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्र की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की सात महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की गई।

मोदी ने बृहस्पतिवार को 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''कल के 'प्रगति' सत्र के दौरान, 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इनमें रेलवे, बिजली और सड़क संपर्क जैसे क्षेत्र शामिल हैं। बंदरगाहों, स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे संस्करण और सामाजिक क्षेत्र की अन्य योजनाओं से संबंधित पहलुओं पर भी चर्चा की गई।''

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की समीक्षा करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि इसे अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श के रूप में काम करना चाहिए, ताकि वे भी आपसी सहयोग, समय पर मंजूरी, प्रौद्योगिकी-आधारित निगरानी और 'मिशन-मोड' में काम करके राज्यों के बीच जल-संबंधी विवादों को सुलझा सकें।

बयान में कहा गया है कि राज्यों को ऐसे ही अन्य अवसरों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, जहां नदी जोड़ो, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और कुशल सिंचाई जैसे कार्यों को एकीकृत तरीके से अपनाया जा सके, ताकि भविष्य के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

'प्रगति' सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) सक्षम, मल्टी-मॉडल प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों को सुचारू रूप से एकीकृत करके सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है।

ये सात महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाएं आर्थिक विकास और जन कल्याण के लिए महत्वपूर्ण हैं और इनकी समीक्षा समयसीमा, अंतर-एजेंसी समन्वय और समय पर मुद्दों के समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हुए की गई।

प्रधानमंत्री ने केन-बेतवा लिंक परियोजना के अलावा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के दूसरे संस्करण की भी समीक्षा की।

मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि बिजली की लागत को कम करने, ऊर्जा सुरक्षा में सुधार करने तथा घरेलू और सामुदायिक स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए छतों पर सोलर पैनल को 'मिशन मोड' में अपनाया जाना चाहिए।

चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र के गड्ढों के नीचे बर्फ होने के पुख्ता संकेत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

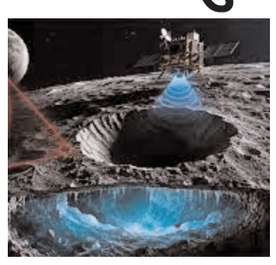

नई दिल्ली/भाषा। एक नए अध्ययन में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के कुछ सबसे ठंडे गड्ढों (क्रेटर) के नीचे बर्फ मौजूद होने के मजबूत संकेत मिलने का दावा किया गया है।

अध्ययन में ''डबल शैडोड क्रेटर्स'' पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया, जो चंद्रमा के स्थायी रूप से छायायुक्त क्षेत्रों (पीएसआर) के भीतर स्थित विशेष प्रकार के गड्ढे हैं।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने बुधवार को जारी एक बयान में कहा कि इस अध्ययन के निष्कर्ष भविष्य के चंद्र अभियानों के लिए महत्वपूर्ण हैं। इससे भविष्य में, पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह की सतह पर उतरने के संभावित स्थलों और स्थानीय संसाधन उपयोग गतिविधियों के लिए बर्फ युक्त क्षेत्रों की पहचान में मदद मिल सकती है।

यह अध्ययन अहमदाबाद स्थित फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी (पीआरएल) के वैज्ञानिकों ने किया है।

केन्या में बालिका विद्यालय में आग लगने से 16 छात्राओं की मौत : अधिकारी

गिलगिल (केन्या)/एपी। मध्य केन्या के एक बालिका विद्यालय के छात्रावास में रात में आग लगने से 16 छात्राओं की मौत हो गई। एक सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी। शिक्षा मंत्री जूलियस ओगाम्बा ने कहा कि 79 अन्य छात्राएं घायल हुई हैं। आग गिलगिल क्षेत्र में स्थित एक आवासीय विद्यालय उतुमिशी गर्ल्स स्कूल के छात्रावासों में लगी। इस विद्यालय में 800 से अधिक छात्राएं पढ़ती हैं। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। ओगाम्बा ने कहा कि अधिकारी इस बात की जांच करेंगे कि स्कूल के अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन किया गया था या नहीं। पीड़ितों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। केन्या रेड क्रॉस ने बताया कि कई छात्राओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और विभिन्न अस्पतालों में उनका इलाज किया जा रहा है। केन्या के आवासीय विद्यालयों में आग लगने की घटनाएं आम हैं। इनमें से कुछ घटनाएं आगजनी के कारण होती हैं, जबकि कुछ बिजली संबंधी खराबियों की वजह से होती हैं।

भारत-चीन के बीच रिश्तों की बहाली के लिए सीमा पर शांति को लेकर सहमति

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) की स्थिति पर ''रचनात्मक'' और ''भविष्य उन्मुख'' वार्ता की। दोनों पक्षों ने माना कि सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने से द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में प्रगति संभव हुई है।

दोनों देशों ने बुधवार को बीजिंग में आयोजित परामर्श एवं समन्वय कार्य तंत्र (डब्ल्यूएमसीसी) की बैठक के दौरान सीमा की स्थिति से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की।

विदेश मंत्रालय ने बातचीत के एक दिन बाद कहा, ''चर्चाएं रचनात्मक और भविष्य उन्मुख रहीं।''

भारत और चीन ने पिछले एक वर्ष में अपने संबंधों को फिर से मजबूत करने के लिए कई उपाय किए हैं, क्योंकि 2020 में गलवान घाटी में हिंसक संघर्ष और उसके बाद चार वर्षों से अधिक समय तक चले सैन्य गतिरोध के कारण दोनों देशों के संबंधों में काफी तनाव आ गया था।

मंत्रालय ने कहा, ''दोनों पक्षों ने भारत-चीन सीमा क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया, जिससे द्विपक्षीय संबंधों को धीरे-धीरे सामान्य बनाने की दिशा में प्रगति संभव हुई है।''

दोनों पक्ष विशेष प्रतिनिधियों की अगली बैठक की ''ठोस तैयारी'' के लिए मिलकर काम करने पर भी सहमत हुए, जो चीन में आयोजित होनी है।

पिछले वर्ष अगस्त में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने नई दिल्ली में विशेष प्रतिनिधियों (एसआर) की वार्ता की थी, जिसमें सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कई परिणाम सामने आए थे।

विदेश मंत्रालय ने डब्ल्यूएमसीसी बैठक पर कहा, ''दोनों पक्षों ने सीमा निर्धारण, सीमा प्रबंधन, तंत्र निर्माण और सीमा पार सहयोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की।''

मंत्रालय ने कहा कि भारतीय पक्ष ने सीमा पार नदियों पर विशेषज्ञ-स्तरीय अगले तंत्र की जल्द बैठक आयोजित करने पर जोर दिया।

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ''दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि वे कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर नियमित संवाद और संपर्क बनाए रखेंगे।

तेलंगाना में ईद-उल-अजहा पूरे धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

हैदराबाद/भाषा। तेलंगाना में बृहस्पतिवार को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने धार्मिक उत्साह के साथ ईद-उल-अजहा का त्योहार मनाया। हैदराबाद के मीर आलम ईदगाह और अन्य ईदगाहों के साथ-साथ राज्य के विभिन्न जिलों में भी बड़ी संख्या में मुसलमानों ने नमाज अदा की। तेलंगाना के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला, मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी और अन्य नेताओं ने ईद-उल-अजहा (बकरीद) के अवसर पर मुस्लिम समुदाय को हार्दिक शुभकामनाएं दीं। राज्यपाल ने कहा, बकरीद इस्लामी आस्था में गहरा महत्व रखती है और इसे गहरी श्रद्धा, आज्ञाकारिता, दान-पुण्य तथा विशेष नमाजों के साथ सम्मान और कुर्बानी की भावना से मनाया जाता है। उन्होंने कहा, यह शुभ त्योहार समाज में शांति, करुणा, सद्भाव और भाईचारे के मूल्यों को मजबूत करे। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि त्याग, करुणा और एकजुटता की भावना हर घर में शांति, खुशी और समृद्धि लाएगी। भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष के. टी. रामाराव ने भी कामना की कि यह त्योहार सभी के लिए शांति, खुशी, समृद्धि और करुणा लेकर आए।

कनाडा के साथ व्यापार समझौते में संवेदनशील क्षेत्रों को अलग रखने पर सहमति : गोयल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

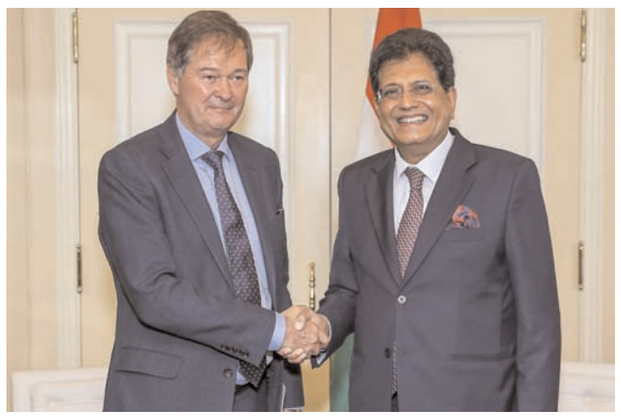

नई दिल्ली/भाषा। भारत और कनाडा ने प्रस्तावित 'व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते' (सीईपीए) पर जारी वार्ता में जल्दी सहमति बन सकने वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है जबकि संवेदनशील क्षेत्रों को फिलहाल अलग रखा जाएगा।

कनाडा की आधिकारिक यात्रा पर गए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दोनों देशों ने बातचीत को व्यावहारिक बनाए रखने पर सहमति जताई है। सीईपीए पर तीसरे दौर की वार्ता इस समय ओटावा में जारी है। गोयल ने एक कार्यक्रम में कहा कि जिन मुद्दों को लेकर किसी भी पक्ष को संवेदनशीलता है, उन्हें समझौते में शामिल करने पर जोर नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा, हमने तय किया है कि बेहतर के चक्कर में अच्छे अवसर नहीं गंवाए जाएंगे। आसान और जल्द परिणाम देने वाले क्षेत्रों पर पहले सहमति बनाई जाएगी। भारत आम तौर पर ऐसे व्यापार समझौतों में कृषि और डेयरी जैसे क्षेत्रों में अपने बाजार तक पहुंच देने से परहेज करता रहा है। दोनों देश इस साल के अंत तक समझौते को अंतिम रूप देने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। साथ ही, द्विपक्षीय व्यापार को मौजूदा 17 अरब डॉलर से बढ़ाकर 2030 तक 50 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। गोयल ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने सरकारी प्रतिनिधियों, उद्योग, निवेश कंपनियों, पेंशन कोष और बीमा क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें कीं। उन्होंने कनाडा की कंपनियों से निवेश का आह्वान करते हुए कहा कि भारत बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप परिवेश है, जहां करीब 2.3 लाख पंजीकृत स्टार्टअप हैं।

हत्या के आरोप में पिता और भाई गिरफ्तार, युवती ने सामने आकर कहा- 'मैं जिंदा हूं'

बुरहानपुर/इंदौर/बुलढाणा/भाषा। मध्यप्रदेश के सीमावर्ती बुरहानपुर जिले की जिस गुमशुदा युवती की हत्या का दावा करते हुए महाराष्ट्र पुलिस ने उसके पिता और भाई को इस महीने गिरफ्तार किया था, वह जिंदा मिली है। मध्यप्रदेश पुलिस के एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। गुमशुदा युवती के सामने आने के बाद महाराष्ट्र पुलिस की जांच पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

बुरहानपुर जिले के खकनार पुलिस थाने के प्रभारी अभिषेक जाधव ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि खड़की गांव में रहने वाली शिवानी बापूराम कलमेकर (26) और अरुण दादू कलमेकर (24) के लापता होने के कुछ दिन बाद उनके परिजनों ने क्रमश: एक मई और नौ मई को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया, ''अरुण की तलाश करते हुए हमें जानकारी मिली कि वह महाराष्ट्र के नाशिक के आस-पास मजदूरी कर रहा है और शिवानी उसके साथ में ही है। इसके बाद प्रेमी जोड़े को ढूंढ लिया गया है।'' जाधव ने बताया कि अंगूठे की छाप, पंचनामा और परिजनों के बयान के जरिये पूरी की गई कानूनी प्रक्रिया से पुष्टि हुई है कि यह युवती शिवानी ही है। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के जलगांव जामोद थाना क्षेत्र में 26 अप्रैल को एक युवती की सिर कटी और आंशिक रूप से जली लाश मिलने के बाद पड़ोसी राज्य की पुलिस ने शिवानी की हत्या का दावा किया था।

अभिषेक जाधव ने बताया कि युवती की हत्या के आरोप में उसके पिता बापूराम कलमेकर (55) और भाई अजय कलमेकर (27) को गिरफ्तार किया था।

ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी से वाहनों की मांग हो सकती है प्रभावित : टीएमपीवी सीईओ

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स (टीएमपीवी) के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) शैलेश चंद्रा ने बृहस्पतिवार को कहा कि ईंधन कीमतों में हुई बढ़ोतरी का कुल खपत एवं वाहन मांग पर पड़ने वाले असर पर नजर रखना जरूरी है और चालू वित्त वर्ष के लिए यात्री वाहन बिक्री 10% बढ़ने के अनुमान में कोई बदलाव अभी जल्दबाजी होगी।

चंद्रा ने टाटा मोटर्स की हैचबैक कार 'टियागो' की अगली पीढ़ी की पेशकश के मौके पर संवाददाताओं के साथ बातचीत में कहा कि ईंधन कीमतों में 10 दिन के भीतर चार बार बढ़ोतरी होने से उपभोक्ता धारणा और मांग पर अंतिम प्रभाव का आकलन करना मुश्किल हो गया है। यात्री वाहन विनिर्माता टीएमपीवी ने 'नेक्स्ट जेन टियागो' को पेट्रोल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक विकल्पों के साथ पेश किया है। इसकी शुरुआती शोरूम कीमत क्रमशः 4.69 लाख रुपए, 5.79 लाख रुपए और 6.99 लाख रुपए है।

चंद्रा ने मौजूदा परिदृश्य के बारे में पूछे जाने पर कहा, ईंधन कीमतों में लगातार बदलाव हो रहा है। पिछले 10 दिन में चार बार कीमतें बढ़ी हैं लिहाजा यह कह पाना मुश्किल है कि यह सिलसिला कहां पर रुकेगा। यह ऐसा पहला कारक है, जो उद्योग पर असर डाल सकता है और दबाव बना सकता है।

चंद्रा ने कहा कि ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी उद्योग के लिए एक संभावित बाधा बन सकती है, लेकिन इसका असर अलग-अलग वाहन खंडों पर अलग-अलग स्तर पर पड़ने का अनुमान है। उन्होंने आगाह किया कि डीजल कीमतों में बढ़ोतरी का मुद्रास्फीति पर गुणक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे उपभोक्ता धारणा और खर्च के रुझान प्रभावित हो सकते हैं। ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी उद्योग के लिए संभावित बाधा बन सकती है, लेकिन इसका असर अलग-अलग वाहन खंडों पर अलग-अलग स्तर पर पड़ेगा। उन्होंने आगाह किया कि डीजल कीमतों में बढ़ोतरी का मुद्रास्फीति पर गुणक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे उपभोक्ता धारणा और खर्च प्रभावित हो सकते हैं।

ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद वाणिज्यिक वाहन उद्योग की मांग मजबूत: अशोक लेलैंड

नई दिल्ली/भाषा। अशोक लेलैंड के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) शेनू अग्रवाल ने बृहस्पतिवार को कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध और ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी जैसी चुनौतियों के बावजूद घरेलू वाणिज्यिक वाहन उद्योग बेहद मजबूत' स्थिति में बना हुआ है।

अग्रवाल ने कंपनी के तिमाही नतीजों की घोषणा संबंधी बैठक में संवाददाताओं से कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों में कटौती और पुराने वाहनों को बदलने से मांग को लगातार समर्थन मिल रहा है। हालांकि, युद्ध की स्थिति आगे कैसे रहती है, इस पर नजर बनी हुई है। ईंधन कीमतों में वृद्धि के वाणिज्यिक वाहन (सीवी) मांग पर असर संबंधी सवाल को लेकर अग्रवाल ने कहा, ''मौजूदा स्थिति में ये दोनों मूलभूत कारक अब भी उद्योग के पक्ष में हैं। हालांकि, खुदरा स्तर पर तेल कीमतों के कारण कुछ व्यवधान जरूर हैं।'' उन्होंने कहा, ''अब तक सरकार ने कीमतों में करीब सात रुपए की वृद्धि की है, जो काफी हद तक वहनीय है और हमें नहीं लगता कि इसका वाणिज्यिक वाहन उद्योग पर कोई बड़ा असर पड़ेगा।''

भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने कहा, पंजाब में 2027 में कमल खिलेगा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चंडीगढ़/भाषा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पंजाब इकाई का अध्यक्ष घोषित किए जाने के तुरंत बाद केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनावों के बाद पार्टी पंजाब में सरकार बनाएगी।

पार्टी नेतृत्व को बड़ी जिम्मेदारी सौंपने के लिए धन्यवाद देते हुए 76 वर्षीय ढिल्लों ने बृहस्पतिवार को कहा कि उनका पहला लक्ष्य पंजाब में भाजपा की सरकार बनाना है। उन्होंने पंजाब की भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि उसने राज्य की जनता से किए गए चुनावी वादे पूरे नहीं किए और वहां ''गुंडा राज'' कायम है। उन्होंने कहा, ''जब पंजाब में हमारी सरकार बनेगी, तब हम इसे हर क्षेत्र में नंबर-1 राज्य बनाएंगे। पश्चिम बंगाल के बाद अब पंजाब में भी कमल खिलेगा।'' भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष ने भारत की ''तेजी से हो रही प्रगति'' का श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को दिया। आम आदमी पार्टी के इस दावे पर कि पंजाब में भाजपा का कोई आधार नहीं है, ढिल्लों ने कहा, ''मुझसे लिखकर ले लीजिए, भाजपा पंजाब में (2027 में) अपनी सरकार बनाएगी। बरनाला से दो बार कांग्रेस विधायक रह चुके ढिल्लों 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे और बाद में उन्हें पार्टी की पंजाब इकाई का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उन्हें पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमरिंदर सिंह का करीबी माना जाता है। सिख समुदाय से आने वाले ढिल्लों, सुनील जाखड़ की जगह लेंगे, जिनका पंजाब भाजपा अध्यक्ष के रूप में तीन साल का कार्यकाल जुलाई में समाप्त हो रहा है। सूत्रों के अनुसार, प्रदेश भाजपा के कुछ नेता पंजाब इकाई की कमान किसी सिख चेहरे को सौंपने की वकालत कर रहे थे।

अमृतसर में आम आदमी पार्टी के नेता पर गोली चलाई गई, हालत गंभीर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

अमृतसर/भाषा। पंजाब में बृहस्पतिवार को आम आदमी पार्टी (आप) के एक नेता को अज्ञात लोगों ने कथित रूप से गोली मार दी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी।

एक अधिकारी ने बताया कि वार्ड नंबर 42 के पार्टी प्रभारी जयपाल सिंह बाऊ पर कुछ महीने पहले कार पार्किंग को लेकर पड़ोसी से हुए विवाद के वजह से कथित तौर पर हमला किया गया।

अधिकारी ने बताया कि बाऊ पर जान से मारने की नीयत से दो गोलियां चलाई गईं। उन्होंने बताया कि गंभीर रूप से घायल बाऊ को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी आपात सर्जरी की गई। बाऊ को आम आदमी पार्टी के अमृतसर दक्षिण से विधायक इंदरबीर सिंह निज्जर का करीबी माना जाता है।

भाजपा सरकार हिंदू-मुस्लिम तनाव भड़काकर अपनी नाकामियां छिपा रही है: वडेट्टीवार

नागपुर/भाषा। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के नेता विजय वडेट्टीवार ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देकर और भावनात्मक मुद्दों को उछालकर अपनी विफलताओं को छिपाने की कोशिश कर रही है, जबकि जनता मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और बढ़ती ईंधन कीमतों की समस्याओं से जूझ रही है। वडेट्टीवार ने यह बात मुंबई के पास कल्याण में दुर्गाड़ी किले में बकरीद की नमाज को लेकर उत्पन्न तनाव के संदर्भ में पत्रकारों से कही। उन्होंने कहा, ध्रुवीकरण और धार्मिक नफरत का यह माहौल अब उनका कारोबार बन गया है। कांग्रेस विधायक दल के नेता ने आरोप लगाया कि जिन मंत्रियों ने दो धर्मों के बीच यह दरार पैदा करने की शुरुआत की है, वे अपने संवैधानिक शपथ का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, लोग महंगाई और बढ़ती ईंधन कीमतों से परेशान हैं, लेकिन सरकार तनाव पैदा करके और लोगों की भावनाओं को भड़काकर ऐसे मुद्दों को छिपाना चाहती है।

वडेट्टीवार ने कहा कि आने वाले डेढ़ महीने में डीजल और पेट्रोल की कीमतें क्रमशः 150 रुपए और 170 रुपए तक पहुंच जाएंगी। उन्होंने दावा किया, देश को खाई में धकेला जा रहा है। देश के गरीब, मध्यम वर्ग के लोग मरने वाले हैं, यह सरकार उन्हें मारने आई है। विमानन ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण उड़ानों की संख्या में कमी के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि सरकार को यह दावा करने के बजाय कि सब कुछ ठीक है, लोगों को यह सच्चाई बतानी चाहिए कि ईंधन की कमी है। वडेट्टीवार ने कहा कि आने वाले दिन लॉकडाउन जैसे हो सकते हैं। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया, भाजपा की राजनीति का उद्देश्य हिंदू-मुस्लिम तनाव को भड़काकर ईंधन की बढ़ती कीमतों और किसानों की समस्याओं जैसे मूल मुद्दों से ध्यान भटकाना है।

भोजशाला परिसर विवाद: उच्चतम न्यायालय में एक और याचिका दाखिल

नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देते हुए एक नई याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि धार जिले का विवादित भोजशाला परिसर देवी सरस्वती का मंदिर है।

उच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि भोजशाला परिसर के प्रशासन और प्रबंधन पर केंद्र और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) निर्णय ले सकते हैं। हिंदू समुदाय भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर मानता है, जबकि मुस्लिम समुदाय 11वीं शताब्दी के इस स्मारक को कमाल मौला मस्जिद कहता है। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित विवादित परिसर एएसआई द्वारा संरक्षित है।

जेब्रान अंसारी नामक एक व्यक्ति ने उच्च न्यायालय के 15 मई के आदेश को चुनौती दी है। इससे पहले, मस्जिद के कार्यवाहक काजी मोइनुद्दीन ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी।

हिंदू पक्ष ने पहले ही उच्चतम न्यायालय में एक कैविएट दायर कर कहा है कि भोजशाला परिसर विवाद मामले में उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ किसी भी अपील पर बिना उसका पक्ष सुने कोई आदेश पारित न किया जाए। जितेंद्र सिंह 'विशेन' द्वारा अधिवक्ता बरुण कुमार सिन्हा के माध्यम से दायर कैविएट में कहा गया, ''उक्त मामले में मुझे सूचना दिए बिना कोई आदेश न दिया जाए।'' विशन इस मामले में छठे याचिकाकर्ता थे, जिस पर इंदौर उच्च न्यायालय की एक पीठ ने फैसला सुनाया।

प्रधान ने कांग्रेस के सीबीएसई परीक्षा संबंधी दावों पर कहा, 'राहुल हताश और तकनीकी प्रगति के विरोधी'

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) परीक्षा प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणियों पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष 'हताश' और 'तकनीकी प्रगति के विरोधी' हैं।

राहुल गांधी ने बुधवार को एक बयान में कहा था कि सीबीएसई परीक्षा परिणामों में 'बड़े पैमाने पर अनियमितताएं' हुई हैं। उन्होंने इस 'पूरे घोटाले' की तह तक जाने के लिए एक स्वतंत्र न्यायिक जांच व एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन की मांग की थी, जिसपर प्रधान ने यह प्रतिक्रिया दी। राहुल ने यह भी आरोप लगाया था कि तेलंगाना की एक संदिग्ध पृष्ठभूमि वाली कंपनी को सीबीएसई द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन का ठेका दिया गया था। प्रधान ने कहा, कल (बुधवार को) सीबीएसई ने इस मामले पर अपना जवाब दिया। यह भारत सरकार की खरीद नीति के अनुरूप है। मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर कोई अनियमितता पाई जाती है, तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता लगातार चुनावी हार से 'हताश' प्रतीत होते हैं। प्रधान ने उन पर सुधारों व तकनीकी प्रगति का विरोध करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, लेकिन जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, वह एक अलग ही मानसिक स्थिति में पहुंच गए हैं। लगातार चुनावी हार से वह हताश दिखते हैं। उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का विरोध किया, वह ईवीएम का विरोध करते थे और उन्होंने डिजिटल इंडिया का विरोध किया।

राउत ने महाराष्ट्र को नीट प्रश्नपत्र लीक मामले का 'केंद्र बिंदु' बताया, फडणवीस पर निशाना साधा

मुंबई/भाषा। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नेता संजय राउत ने बृहस्पतिवार को कहा कि महाराष्ट्र वर्ष 2026 के लिए आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) के प्रश्नपत्र लीक मामले का 'केंद्र बिंदु' बनकर उभरा है। राउत ने यह भी पूछा कि क्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 'लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद करने' की जिम्मेदारी लेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से अधिकांश महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, जिसमें लातूर, पुणे और अहिल्यानगर शामिल हैं।

राउत ने यहां पत्रकारों से कहा, ''महाराष्ट्र परीक्षा (नीट) का प्रश्नपत्र लीक करने वाले गिरोह का केंद्र बनकर उभरा है। अगर इस नेटवर्क की जड़ें लातूर से पुणे तक फैली हुई हैं तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जवाब देना होगा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है।'' उन्होंने कहा कि प्रश्नपत्र लीक के कारण देश भर के लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। प्रश्नपत्र लीक नेटवर्क से कथित तौर पर जुड़े एक आरोपी की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए राज्यसभा सदस्य ने दावा किया कि इस गिरोह के महाराष्ट्र से संबंध थे। उन्होंने पूछा कि सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन राज्य तंत्र और पुलिस इन घटनाक्रमों से अनभिज्ञ क्यों थे?

होर्मुज पर निर्भरता घटाने के लिए आईएमईसी, हिंद-प्रशांत मार्ग अहम: ईवाई

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। देश को होर्मुज जलडमरूमध्य पर निर्भरता कम करने के लिए अपने व्यापार मार्गों में विविधता लाने और भारत-पश्चिम एशिया-यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईसी) तथा मलक्का जलडमरूमध्य के जरिये हिंद-प्रशांत मार्ग जैसे वैकल्पिक संपर्क गलियारों के विकास में तेजी लाने की जरूरत है। वित्तीय परामर्श कंपनी ईवाई की एक रिपोर्ट में यह कहा गया।

ईवाई की 'इकॉनमी वॉच' की मई रिपोर्ट में कहा गया है कि पश्चिम एशिया संकट और बदलती वैश्विक व्यापार एवं आर्थिक व्यवस्था से उत्पन्न दबावों को देखते हुए भारत को अपनी वृद्धि रणनीति में बदलाव करना पड़ सकता है, ताकि मध्यम और दीर्घकालिक वृद्धि पथ को नुकसान से बचाया जा सके।

इस महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोने के आयात में कमी, विदेशी यात्राओं में कटौती और घरेलू ईंधन खपत घटाने जैसे मितव्ययिता उपायों का आह्वान किया था।

रिपोर्ट में कहा गया कि भविष्य में भारत को अप्रत्याशित आर्थिक झटकों और कमजोरियों से निपटने की तैयारी करनी होगी।

इसके तहत सरकार कच्चे तेल, एलपीजी, उर्वरक, प्रसंस्कृत एवं अप्रसंस्कृत दुर्लभ खनिज पदार्थों, दवाओं और महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरणों के रणनीतिक भंडार तैयार करने पर विचार कर सकती है।

रिपोर्ट के अनुसार, अप्रत्याशित परमाणु और जैविक खतरों के प्रभाव को कम करने के लिए दोहरे उपयोग वाले बुनियादी ढांचे के निर्माण तथा चालू खाते और राजकोषीय घाटे को टिकाऊ स्तर पर बनाए रखने की रणनीति पर भी नए सिरे से काम करने की जरूरत है।

इसमें कहा गया कि हरित और परमाणु ऊर्जा, विशेष रूप से थोरियम आधारित उत्पादन की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाने, स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास और इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर तेज बदलाव की भी आवश्यकता हो सकती है।

रिपोर्ट में कहा गया कि पेट्रोलियम स्रोतों में हालिया विविधीकरण से भारत की होर्मुज जलडमरूमध्य पर निर्भरता कुछ कम हुई है।

रिपोर्ट के अनुसार, ''भारत को व्यापार के वैकल्पिक मार्गों में और विविधता लाने तथा भारत-पश्चिम एशिया-यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईसी) और मलक्का जलडमरूमध्य वाले हिंद-प्रशांत गलियारे के विकास में तेजी लाने की दिशा में काम करना चाहिए।''

रुपए को अभी और गिरने दे आरबीआई, तरलता प्रबंधन को मिले प्राथमिकता: पूर्व गवर्नर सुब्बाराव

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव ने कहा है कि बाहरी दबावों को झेलने के लिए केंद्रीय बैंक को रुपए में कुछ और गिरावट आने देनी चाहिए और महंगाई का जोखिम बढ़ने पर ब्याज दर बढ़ाने के बजाय तरलता प्रबंधन जैसे उपायों को प्राथमिकता देनी चाहिए।

सुब्बाराव ने पीटीआई-भाषा के साथ खास बातचीत में कहा कि विनिमय दर को संभालने के लिए मौद्रिक नीति का सहारा केवल 'अंतिम उपाय' के तौर पर लिया जाना चाहिए। वर्ष 2008 से लेकर 2013 तक आरबीआई के गवर्नर रह चुके सुब्बाराव ने कहा, ''रुपए के स्तर को बचाने के बजाय उसे परिस्थितियों के अनुरूप समायोजित होने देना चाहिए, क्योंकि कमजोर रुपया बाहरी झटकों को झेलने में मदद करता है।'' इसके साथ ही उन्होंने कहा, ''यदि आरबीआई को ऐसा लगता है कि महंगाई की स्थिति इसकी मांग करती है, तो वह मौद्रिक नीति को सख्त कर सकता है।''

भू-राजनीतिक अनिश्चितता और पश्चिम एशिया संकट के कारण रुपया दबाव में है और इस महीने की शुरुआत में यह डॉलर के मुकाबले 97.15 के रिकॉर्ड निचले स्तर तक पहुंच गया। पश्चिम एशिया संकट की शुरुआत से रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अब तक करीब पांच प्रतिशत गिर चुका है जबकि इस वर्ष की शुरुआत से इसमें 6.1 प्रतिशत और एक साल के भीतर 10 प्रतिशत से अधिक गिरावट आई है। सुब्बाराव ने कहा कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के सामने संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि दरों में कटौती से महंगाई और विनिमय दर पर दबाव बढ़ सकता है, जबकि आक्रामक दर बढ़ोतरी से आर्थिक वृद्धि प्रभावित हो सकती है। सुब्बाराव ने कहा कि मौजूदा स्थिति में दर बढ़ाने के बजाय इंतजार करना और महंगाई के रुझान का आकलन करना बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि यदि महंगाई में तेज बढ़ोतरी होती है, तो पहले तरलता या नकदी प्रबंधन के जरिये सख्ती की जा सकती है, न कि सीधे दर बढ़ाकर।

कांग्रेस आलाकमान के निर्देश पर मैंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है : सिद्दरामय्या

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। कांग्रेस नेता सिद्दरामय्या ने बृहस्पतिवार को कहा कि दो दिन पहले कांग्रेस आलाकमान द्वारा दिये गये निर्देश के बाद उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उन्हें दो बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में लोगों की सेवा करने का अवसर देने के लिए कांग्रेस नेतृत्व – सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी – को धन्यवाद दिया । सिद्दरामय्या ने यहां लोक भवन में राज्यपाल के विशेष सचिव को अपना इस्तीफा सौंपने के शीघ्र बाद उपमुख्यमंत्री और अपने उत्तराधिकारी डी के शिवकुमार के साथ प्रेसवार्ता को संबोधित किया।

राज्यपाल थावरचंद गहलोत की अनुपस्थिति में विशेष सचिव प्रभु शंकर ने सिद्दरामय्या का इस्तीफा लिया। सिद्दरामय्या ने पत्रकारों से कहा, मैंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राज्यपाल संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार उनका इस्तीफा स्वीकार कर लेंगे। उन्होंने कहा, मैंने बार-बार कहा था कि जब भी पार्टी आलाकमान मुझे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने को कहेगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा। आलाकमान ने मुझे दो दिन पहले पद छोड़ने का निर्देश दिया था, जिसके अनुसार मैंने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया।

उन्होंने कहा, मुझे दो बार कर्नाटक के लोगों की सेवा करने का मौका मिला जिसके लिए मैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे को धन्यवाद देता हूं। जब सिद्दरामय्या अपना इस्तीफा सौंपने लोकभवन गये तब उनके साथ शिवकुमार एवं अन्य मंत्रिमंडलीय सहयोगी भी थे। सिद्दरामय्या ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि राज्यपाल संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लेंगे।

हालांकि उन्होंने कहा, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे राज्यसभा सीट की पेशकश की, लेकिन मैंने विनम्रतापूर्वक इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि मुझे राष्ट्रीय राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है।

उन्होंने कहा, मैं राज्य की राजनीति में बना रहूंगा क्योंकि विधायक के रूप में मेरा कार्यकाल अभी दो साल बाकी है। सिद्दरामय्या ने कहा, 550 वादों में से अब तक करीब 300 पूरे किए जा चुके हैं। पांच गारंटी भी लागू की गई हैं। मैं किए गए वादों से कभी पीछे नहीं हटा। उन्होंने कहा, विपक्ष ने मेरे खिलाफ कई झूठी कहानियां गढ़ीं। मैं न कभी पैसे के पीछे भागा और न ही संपत्ति बनाने की लालसा रही, मेरा राजनीतिक जीवन एक खुली किताब की तरह है ।

उन्होंने कहा, मैं अपनी आखिरी सांस तक सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ूंगा। मैं संविधान के खिलाफ काम करने वालों के खिलाफ लड़ूंगा। मई 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए सिद्दरामय्या और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवकुमार के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा थी। पार्टी ने बाद में शिवकुमार को (मुख्यमंत्री पद छोड़ देने के लिए) मना लिया और उन्हें उपमुख्यमंत्री बना दिया।

उस समय खबरें आयीं कि बारी-बारी से मुख्यमंत्री बनने के फार्मूले' पर सहमति बनी है, जिसके तहत शिवकुमार ढाई साल बाद मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन पार्टी या दोनों नेताओं की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी। आज त्यागपत्र देने से पहले सिद्दरामय्या ने अपने सरकारी निवास पर मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के लिए आयोजित जलपान में मंत्रियों को पद छोड़ने के अपने फैसले से अवगत कराया और यह भी कहा कि कांग्रेस आलाकमान के निर्देशानुसार उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जलपान पर हुई इस बैठक की तस्वीर साझा की गई जिसमें सिद्दरामय्या भावुक शिवकुमार को गले लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक अन्य तस्वीर में, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार शिवकुमार सिद्दरामय्या के पैर छूते और उनका आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं।

कांग्रेस आलाकमान द्वारा सिद्दरामय्या को राज्य में नेतृत्व परिवर्तन के लिए मार्ग प्रशस्त करने को कहा गया था और उन्हें राज्यसभा सीट के साथ पार्टी में एक केंद्रीय भूमिका की पेशकश की गयी थी। उसके बाद सिद्दरामय्या ने आज इस्तीफा दे दिया। कुछ सूत्रों के अनुसार, सिद्दरामय्या ने पद छोड़ने का फैसला इसलिए किया क्योंकि यह संदेश सीधे पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी की ओर से आया था।

सिद्दरामय्या और शिवकुमार को मंगलवार को पार्टी ने दिल्ली बुलाया था, जहां कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पार्टी महासचिव के सी वेणुगोपाल और सुरजेवाला की उपस्थिति में लगातार बैठकें हुईं। इसी बीच, सिद्दरामय्या के समर्थकों ने राज्य के कई हिस्सों में उनके इस्तीफे के विरोध में प्रदर्शन किया। यहां सिद्दरामय्या के सरकारी आवास पर भावुक दृश्य देखने को मिले, जब समर्थकों के एक बड़े समूह ने उन्हें घेर लिया और उनसे इस्तीफा न देने की अपील की। ङ्कङ्कमुख्यमंत्री ने उन्हें सांत्वना देने का प्रयास किया। डी के शिवकुमार के अगले मुख्यमंत्री बनने की खबर के बाद उनके आवास के पास जश्न का माहौल था।

सिद्दरामय्या ने मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ नाश्ता किया

बेंगलूरु/दक्षिण भारत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या ने बृहस्पतिवार को अपने सरकारी आवास पर मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ नाश्ता किया। उपमुख्यमंत्री एवं मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार डी.के. शिवकुमार तथा अन्य मंत्री भी इस बैठक में शामिल हुए। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक तस्वीर में सिद्दरामय्या, शिवकुमार को गले लगाते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार शिवकुमार, सिद्दरामय्या के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते दिखाई दे रहे हैं।

ऐसी खबरें हैं कि सिद्दरामय्या इसी बैठक में मुख्यमंत्री पद छोड़ने की घोषणा कर सकते हैं ताकि शिवकुमार के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो सके। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के सूत्रों के अनुसार, पार्टी आलाकमान द्वारा राज्य में नेतृत्व परिवर्तन का रास्ता बनाने के संकेत दिए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मिलने का समय मांगा। उन्होंने यह भी कहा कि वह इस मुद्दे पर बृहस्पतिवार को बयान देंगे।

हालांकि, लोक भवन सूत्रों ने कहा कि सिद्दरामय्या ने अब तक राज्यपाल से मिलने के लिए समय नहीं मांगा है। सूत्रों के अनुसार, राज्यपाल निजी कारणों से अपने गृह नगर इंदौर गए हुए हैं। दक्षिणी राज्य में नए मुख्यमंत्री को लेकर सियासी हलचल तेज होने के बीच कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने बुधवार को स्पष्ट किया कि पार्टी ने राज्य में विधायक दल की कोई बैठक नहीं बुलाई है और अब तक कोई अन्य फैसला भी नहीं लिया गया है। उन्होंने मीडिया से इस मुद्दे पर अटकलें नहीं लगाने का अनुरोध किया।

विधायक दल अपने नेता का चुनाव करता है जो स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री का दावेदार होता है। बुधवार को यहां पहुंचे सुरजेवाला ने सिद्दरामय्या और अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात की।

खबरें हैं कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने सिद्दरामय्या से कथित तौर पर नेतृत्व परिवर्तन का रास्ता साफ करने को कहा और उन्हें राज्यसभा सीट के साथ पार्टी में केंद्रीय भूमिका की पेशकश की। हालांकि सूत्रों के अनुसार सिद्दरामय्या ने अभी तक इस केंद्रीय भूमिका को स्वीकार नहीं किया है। सूत्रों का यह भी कहना है कि चूंकि यह संदेश सीधे राहुल गांधी की ओर से आया है, इसलिए सिद्दरामय्या पद छोड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं।

मुख्यमंत्री पहले भी कई बार कह चुके हैं कि अगर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा तो वह पद छोड़ देंगे। सिद्दरामय्या और शिवकुमार को मंगलवार को पार्टी ने दिल्ली बुलाया था, जहां कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पार्टी के महासचिव के. सी. वेणुगोपाल तथा रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ लगातार बैठकें हुईं। इस बीच, कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग समुदाय महासंघ ने कांग्रेस और उसके शीर्ष नेतृत्व को चेतावनी दी कि अगर सिद्धारमैया को हटाया गया तो पार्टी को इसके परिणाम भुगतने होंगे।

कांग्रेस आलाकमान के राज्यसभा सीट के प्रस्ताव को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया : सिद्दरामय्या

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके सिद्दरामय्या ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि उन्होंने कांग्रेस आलाकमान द्वारा दी गई राज्यसभा सीट का प्रस्ताव 'विनम्रतापूर्वक अस्वीकार' कर दिया। सिद्दरामय्या ने कहा कि वह वरुणा विधानसभा क्षेत्र के विधायक के रूप में शेष दो वर्षों तक सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। सिद्दरामय्या ने कहा, आलाकमान ने मुझे राज्यसभा जाने के लिए कहा। मैंने इसे विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया। मुझे राष्ट्रीय राजनीति में कोई रुचि नहीं है। उन्होंने यहां लोक भवन में राज्यपाल के विशेष सचिव को अपना इस्तीफा सौंपने के तुरंत बाद अपने आवासीय कार्यालय 'कृष्णा' में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया और कहा कि वह राज्य की राजनीति से जुड़े रहेंगे।

सिद्दरामय्या ने कहा, मैं राज्य की राजनीति में ही रहूंगा। लोगों ने मुझे पांच साल के लिए चुना है और अभी दो साल बाकी हैं। तब तक मैं कर्नाटक के लोगों और अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के लिए काम करता रहूंगा। राजनीतिक भविष्य के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस नेता ने कहा कि वह राजनीति में सक्रिय रहेंगे और सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। जब उनसे उनके इस्तीफे के असली कारण के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह शुरू से ही कहते रहे हैं कि जब भी आलाकमान उनसे इस्तीफा देने को कहेगा, वह पद छोड़ देंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से कोई दबाव था, तो उन्होंने कहा, कैसा दबाव? जैसे ही उन्होंने (आलाकमान ने) मुझसे ऐसा करने को कहा मैंने इस्तीफा दे दिया।

सिद्दरामय्या के समर्थकों ने इस्तीफे के उनके फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या के समर्थकों ने पद से इस्तीफा देने के उनके फैसले के खिलाफ बृहस्पतिवार को राज्य के कई हिस्सों में प्रदर्शन किया। बेंगलूरु में सिद्दरामय्या के आधिकारिक आवास 'कावेरी' के बाहर भावुक दृश्य देखने को मिले, जहां बड़ी संख्या में समर्थक जमा हो गए और मुख्यमंत्री को घेरते हुए उनसे इस्तीफा न देने का आग्रह किया। इस दौरान, सिद्दरामय्या अपने समर्थकों को सांत्वना देने की कोशिश करते नजर आए। जब सिद्दरामय्या राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने के लिए लोक भवन की ओर रवाना होने लगे, तो कुछ समर्थकों ने उनका वाहन रोकने का भी प्रयास किया।

शिवमोग्गा शहर में सिद्दरामय्या के समर्थकों ने शिवप्पा नायक सर्कल पर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व मुख्य रूप से कुरुबा समुदाय के सदस्यों ने किया। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के सिद्दरामय्या के फैसले पर नाखुशी जाहिर करते हुए प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाए। उन्होंने सिद्दरामय्या से पद पर बने रहने की मांग करते हुए उनके समर्थन में नारे भी लगाए। यादगिर में सिद्दरामय्या के कट्टर समर्थक राजकुमार गनीर ने सुभाष चंद्र सर्कल के पास मौन रखकर प्रदर्शन किया। गनीर ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के सिद्दरामय्या के फैसले पर दुख जाहिर किया।

कर्नाटक के कानून मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि सिद्दरामय्या ने उन्हें और अन्य मंत्रियों को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के अपने फैसले की जानकारी दी और बताया कि उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार उनके उत्तराधिकारी होंगे। पाटिल के मुताबिक, पार्टी आलाकमान ने शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने के निर्देश दिए हैं और इस सिलसिले में विधायक दल की बैठक में उचित प्रक्रियात्मक कदम उठाए जाएंगे।

सिद्दरामय्या ने इस्तीफा देने के बाद धन्यवाद देते हुए भावुक पोस्ट किया

बेंगलूरु। कांग्रेस नेता सिद्दरामय्या ने बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कर्नाटक की जनता को राज्य प्रशासन के प्रमुख के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा दिये गये प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद देते हुए सोशल मीडिया पर भावुक संदेश लिखा। सिद्दरामय्या ने 'एक्स' पर एक तस्वीर साझा की, जिसमें वह एक सभा के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं और आभार व्यक्त कर रहे हैं।

उन्होंने लिखा, धन्यवाद। आपका प्यार। आपका भरोसा। मेरी सदैव की शक्ति। यह संदेश तस्वीर पर उनके हस्ताक्षर के साथ दिखाई दिया।सिद्दरामय्या ने मुश्किल समय में साथ देने के लिए लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, मैं कर्नाटक के लोगों के सामने सिर झुकाता हूंलाखों स्नेही हृदयों ने मुझे अपने ही एक सदस्य की तरह माना, मुझे आशीर्वाद दिया, मेरा हौसला बढ़ाया, मेरी गलतियों को सुधारा, मुश्किल समय में मेरा साथ दिया और इस लंबी यात्रा में मेरा हाथ थामे रखा। आज मैं जो कुछ भी हूं, आप सबकी वजह से ही हूं। सिद्दरामय्या ने कहा कि संविधान उनका धर्म है और जनता उनकी ईश्वर है। उन्होंने यह भी कहा कि उनका इस्तीफा केवल मुख्यमंत्री पद से है, न कि सार्वजनिक जीवन या जनता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता से।

इस्तीफे के बाद सिद्दरामय्या कांग्रेस नेतृत्व से मिलने दिल्ली रवाना

बेंगलूरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के कुछ ही समय बाद सिद्दरामय्या बृहस्पतिवार को नयी दिल्ली के लिए रवाना हो गए, जहां वह अपने उत्तराधिकारी और मंत्रिमंडल गठन की प्रक्रिया के संबंध में कांग्रेस आलाकमान के साथ चर्चा कर सकते हैं। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। खबरों के अनुसार, उपमुख्यमंत्री और सिद्दरामय्या के संभावित उत्तराधिकारी डी के शिवकुमार भी आज बाद में राष्ट्रीय राजधानी के लिए रवाना होंगे। शिवकुमार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं। मीडिया के साथ साझा की गई सिद्धारमैया की यात्रा योजना के अनुसार, वह आज रात दिल्ली पहुंचेंगे और उनकी वापसी यात्रा के समय को 'खुला' रखा गया है।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, सिद्दरामय्या की दिल्ली यात्रा के दौरान आलाकमान के साथ विधायक दल के नये नेता के चयन, मंत्रिमंडल संरचना और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष समेत विभिन्न विषयों/बातों पर चर्चा होने की संभावना है।

इससे पूर्व सिद्दरामय्या ने लोक भवन में राज्यपाल के विशेष सचिव को अपना इस्तीफा सौंप दिया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत की अनुपस्थिति में विशेष सचिव प्रभु शंकर ने उनका इस्तीफा ग्रहण किया। इससे पहले दिन में अपने सरकारी आवास पर मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के लिए आयोजित जलपान के दौरान, सिद्दरामय्या ने मंत्रियों को अपने पद से इस्तीफा देने के फैसले की जानकारी दी और कहा कि कांग्रेस आलाकमान के निर्देशों के अनुसार, उपमुख्यमंत्री शिवकुमार उनके उत्तराधिकारी होंगे। बैठक में मौजूद रहे कई मंत्रियों ने यह बात कही।

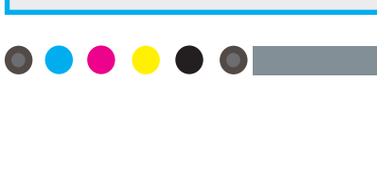

'जनता परिवार' के वफादार से कांग्रेस के कद्दावर नेता तक

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। दो दशक से अधिक समय तक 'जनता परिवार' के वफादार नेताओं में शुमार सिद्दरामय्या अतीत में कांग्रेस के खिलाफ अपने मुखर रुख के लिए जाने जाते थे। हालांकि, 2006 में कांग्रेस में शामिल होने के बाद वह न सिर्फ खुद को पार्टी के एक कद्दावर नेता के रूप में स्थापित करने में कामयाब हुए, बल्कि सबसे लंबे समय तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद पर सेवा देने की उपलब्धि भी हासिल की। नौ बार विधायक रहे सिद्दरामय्या (77) ने मुख्यमंत्री के रूप में पांच साल का कार्यकाल पूरा करने और एक शानदार विदाई पाने की अपनी महत्वाकांक्षा कभी छिपाई नहीं। हालांकि, कांग्रेस आलाकमान ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए सिद्दरामय्या से उनके कार्यकाल की समाप्ति के लगभग दो साल पहले ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए कह दिया।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान सिद्दरामय्या ने सात जनवरी 2026 को सबसे लंबे समय तक राज्य के शीर्ष पद (मुख्यमंत्री) पर रहने का वरिष्ठ कांग्रेस नेता देवराज उर्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सिद्दरामय्या की तरह ही देवराज भी मैसूर से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में अपने दो कार्यकाल के दौरान कुल 2,792 दिन तक इस पद पर सेवाएं दी थीं। एक गरीब किसान परिवार से आने वाले सिद्दरामय्या 1980 के दशक की शुरुआत से लेकर 2005 तक कांग्रेस के कट्टर विरोधी थे। हालांकि, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली जनता दल-सेक्युलर (जद-एस) से निष्कासन के बाद उन्होंने 2006 में उसी पार्टी में शामिल होने का फैसला किया, जिसके वह कट्टर विरोधी हुआ करते थे।

कानून की डिग्री रखने वाले सिद्दरामय्या ने एक समय राजनीति से संन्यास लेने की बात कही थी। उन्होंने वकालत के पेशे में लौटने के बारे में भी सोचा था। सिद्दरामय्या ने खुद की पार्टी बनाने की संभावनाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इसके लिए उनके पास न तो धन है और न ही बल। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) दोनों ने सिद्दरामय्या को अपने पाले में लाने की कोशिश की। हालांकि, सिद्दरामय्या ने कहा कि वह भाजपा की विचारधारा से इत्तफाक नहीं रखते हैं और अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। उनके इस कदम को उस समय कल्पना से परे माना गया था।

'जनता परिवार' के सदस्य के रूप में सिद्दरामय्या राम मनोहर लोहिया द्वारा प्रतिपादित समाजवाद से प्रभावित थे। उन्होंने वकालत का पेशा छोड़कर राजनीति की दुनिया में कदम रखा और तालुक बोर्ड के सदस्य के रूप में सियासी सफर की शुरुआत की।कांग्रेस में सिद्दरामय्या का धैर्य और दृढ़ता रंग लाई तथा 2013 में कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनने का उनका सपना साकार हो गया। वह मई 2018 तक इस पद पर रहे। 2023 में कर्नाटक की सत्ता में कांग्रेस की वापसी के बाद उन्हें एक बार फिर मुख्यमंत्री पद पर सेवा देने का मौका मिला।

कर्नाटक में 2004 में हुए विधानसभा चुनाव में खंडित जनादेश के बाद कांग्रेस और जद(एस) ने गठबंधन सरकार बनाई। उस समय जद(एस) का हिस्सा रहे सिद्दरामय्या को राज्य का उपमुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि कांग्रेस के एन धरम सिंह को मुख्यमंत्री पद सौंपा गया। सिद्दरामय्या को हमेशा इस बात का मलाल रहा कि उस समय उनके पास मुख्यमंत्री बनने का मौका था, लेकिन देवेगौड़ा ने उनकी संभावनाओं पर पानी फेर दिया। कर्नाटक की तीसरी सबसे बड़ी जाति कुरुबा से ताल्लुक रखने वाले सिद्दरमैया ने इस घटनाक्रम के बाद 2005 में खुद को पिछड़े वर्गों के नेता के रूप में पेश करने का फैसला किया।

पानी-बिजली की आपूर्ति में कोई भी कोताही स्वीकार नहीं, समस्याओं का त्वरित समाधान हो : डॉ. बैरवा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। उपमुख्यमंत्री एवं राजसमंद प्रभारी मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा के मुख्य आतिथ्य में गुरुवार दोपहर जिला परिषद सभागार, राजसमंद में जिला स्तरीय अधिकारियों की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में उपमुख्यमंत्री डॉ बैरवा द्वारा राज्य सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं, समर कंटीन्जेसी प्लान, जल संचय-जन भागीदारी अभियान तथा वंदे गंगा (जल संरक्षण-जन अभियान) की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विकास कार्यों, पेयजल व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, ग्रामीण विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण किए जाएं तथा योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा के दौरान उपमुख्यमंत्री डॉ. बैरवा ने नवीन परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित करने, कुसुम योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एवं शहरी, स्वामित्व योजना, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना तथा जल जीवन मिशन की प्रगति की जानकारी ली। पंच गौरव योजना के अंतर्गत संचालित लखपति दीदी, सोलर दीदी, ड्रोन दीदी, बैंक सखी, कृषि सखी एवं पशु सखी कार्यक्रमों की भी समीक्षा की गई।

बैठक में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0, अटल ज्ञान केंद्र, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं अटल प्रगति पथ सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली गई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी, मिशन हरियालो राजस्थान, अमृत योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना तथा मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की समीक्षा कर विभागीय अधिकारियों को समयबद्ध कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।

उपमुख्यमंत्री डॉ. बैरवा ने कहा कि सभी विभाग राज्य सरकार की मंशा अनुसार हर योजना और कार्यक्रम में प्रत्येक व्यक्ति को लाभान्वित करें तथा जन समस्याओं का त्वरित समाधान करें। साथ ही निर्देश दिए कि पेयजल और बिजली आपूर्ति से जुड़े किसी भी कार्य में अनावश्यक देरी न हो तथा शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अवैध जल कनेक्शनों पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए ताकि ग्रीष्म ऋतु में आमजन को पानी मिलने में कठिनाई न हो।

बैठक में सांसद महिमा कुमारी मेवाड़, राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी, नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़, जिलाध्यक्ष जगदीश पालीवाल आदि ने पेयजल सप्लाई, विशेष रूप से बाघेरी परियोजना से पेयजल सप्लाई, विद्युत सप्लाई, आरडीएसएस, फार्म पॉण्ड, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं, आरवीपीएनएल आदि से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जिन पर उपमुख्यमंत्री डॉ बैरवा ने हाथों-हाथ पीएचईडी को सभी शिकायतों पर जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश दिए।

अजमेर में पूर्व सरपंच समेत परिवार के चार लोगों की हत्या

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान के अजमेर जिले में एक पूर्व सरपंच समेत उनके परिवार के चार सदस्यों की कथित तौर पर हत्या करने के बाद शवों को गाड़ी में रखकर जलाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस को संदेह है कि इस मामले में पूर्व सरपंच की पहली पत्नी और कुछ अन्य लोगों की भूमिका हो सकती है। उसने बताया कि यह घटना अजमेर शहर से करीब 60 किलोमीटर दूर श्रीरामपुरा गांव में बृहस्पतिवार तड़के सामने आई, जब राजमार्ग पर एक स्कॉर्पियो जलती हुई मिली। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान पूर्व सरपंच राम सिंह चौधरी, उनकी मां पूसी देवी, पत्नी सूर्यज्ञान देवी और भतीजी महिमा चौधरी के रूप में हुई है।

उसने बताया कि जले हुए वाहन के अंदर तीन शव मिले, जबकि एक शव समीप खेत से बरामद किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अगरवाला ने बताया कि शुरुआत में यह मामला वाहन में आग लगने से हुई दुर्घटना का लग रहा था, लेकिन प्रारंभिक जांच में हत्या की आशंका सामने आई है।

उन्होंने बताया कि गाड़ी चौधरी के घर से करीब 500 मीटर दूर मिली। जब पुलिस घर पहुंची तो राम सिंह की पहली पत्नी ने बताया कि वह अपनी मां को लेकर अस्पताल गए थे, क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी और सीने में दर्द हो रहा था।

इस बीच, पुलिस को शवों पर चोट के निशान मिले और घर के अंदर खून के धब्बे भी दिखाई दिए जिसके बाद हत्या के पहलू से जांच शुरू की गई। सबूत जुटाने के लिए फॉरेंसिक प्रयोगशाला की टीम को मौके पर बुलाया गया। अगरवाला ने बताया कि राम सिंह की दो पत्नियां थीं और इस बात को लेकर परिवार में विवाद था। उन्होंने बताया कि जांच में यह भी सामने आया कि पहली पत्नी और बच्चों की राम सिंह तथा उनकी मां के साथ कहासुनी हुई थी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रथम दृष्टया राम सिंह की पहली पत्नी और बच्चों ने देर रात चारों की हत्या कर दी और बाद में शवों को राजमार्ग पर ले जाकर गाड़ी में आग लगा दी, ताकि इसे दुर्घटना का रूप दिया जा सके। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और अन्य लोगों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है। उन्होंने बताया कि कुछ आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में विद्युत प्रसारण एवं वितरण तंत्र हुआ सुदृढ़

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार के बेहतर प्रबंधन एवं दूरगामी निर्णयों के फलस्वरूप प्रदेश में विद्युत प्रसारण एवं वितरण तंत्र में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं, जिसके फलस्वरूप भीषण गर्मी के दौर में भी घरेलु, कृषि उपभोक्ताओं सहित उद्योगों को निर्बाध एवं पर्याप्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। वहीं, जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा सतत मॉनिटरिंग एवं नवाचारों से विद्युत उपभोक्ताओं की शिकायतों में उल्लेखनीय कमी भी आई है।

राज्य सरकार वर्ष 2027 तक दिन के समय में किसानों को बिजली उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसके लिए विद्युत प्रसारण तंत्र का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। राज्य सरकार के अब तक के कार्यकाल में प्रदेशभर में 33 केवी के 444 सब स्टेशन स्थापित किए गए हैं। वहीं, 211 सब स्टेशन कार्य प्रगतिरत हैं। इसी प्रकार, 400, 220 और 132 केवी के 59 जीएसएस स्थापित किए गए हैं और 145 जीएसएस का कार्य प्रगतिरत हैं। वहीं, सौर ऊर्जा संयंत्र (कुसुम-ए, सी और रूफटॉप सहित) के वृहद नेटवर्क के जरिए लगभग 7 हजार 376 मेगावाट तथा कोयला आधारित तापीय परियोजनाओं से 7 हजार 830 मेगावाट विद्युत क्षमता उपलब्ध है।

तापमान में अत्यधिक बढ़ोतरी के कारण ट्रिपिंग अथवा फॉल्ट की आशंका से निपटने तथा उपभोक्ताओं को व्यवधान रहित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए डिस्कॉम्स कंपनियों में कार्ययोजना के तहत अलर्ट मोड पर कार्य किया है। गर्मी आने से पहले डिस्कॉम्स ने ट्रांसफार्मरों में 13 हजार 473 एमवीए की क्षमता आवर्धन, 11 केवी और 33 केवी के 4 हजार 815 फीडरों का विभाजन, लगभग 5 हजार सर्किट लाइनों का अतिरिक्त नेटवर्क विस्तार करने के साथ ही 3 हजार 682 जीएसएस के रखरखाव का कार्य व्यापक स्तर पर किया।

वहीं, उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए विद्युत वितरण निगमों ने प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र विकसित किया गया है। इस तंत्र में टोल फ्री कॉल सेंटर्स, ग्राहक सेवा केन्द्र, केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष के साथ-साथ लगभग 1129 फॉल्ट रेक्टिफिकेशन टीम उपभोक्ताओं की शिकायतों पर रेपिड एक्शन लेते हुए उपभोक्ताओं को राहत पहुंचा रही है।

परिणामस्वरूप शिकायतों एवं उनके निस्तारण के संबंध में उल्लेखनीय कमी आई है। जयपुर, अजमेर और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में 1 अप्रेल 2025 से 20 मई 2025 तक नो करंट की लगभग 3 लाख 52 हजार शिकायतें दर्ज हुई, जो इस कालखण्ड में वर्ष 2026 के दौरान लगभग 41 हजार की कमी के साथ 3 लाख 11 हजार ही रह गई हैं। यह दर्शाता है कि विद्युत आपूर्ति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

जनभागीदारी से जीतेंगे टीबी की जंग : शर्मा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राजस्थान टीबी मुक्त होने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के टीबी मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी दिशा में संचालित 'टीबी मुक्त भारत अभियान-100 दिवसीय विशेष अभियान' में राजस्थान ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। इस वर्ष 24 मार्च को शुरू हुए इस अभियान में मात्र दो माह में प्रदेश में करीब 19 लाख व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की गई है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 'निरामय राजस्थान' के विजन के तहत टीबी जैसी गंभीर बीमारी के उन्मूलन के लिए व्यापक स्तर पर स्क्रीनिंग, शीघ्र जांच, जनजागरूकता, पोषण सहायता एवं सामुदायिक सहभागिता को प्राथमिकता दी जा रही है। जनभागीदारी, तकनीक एवं संवेदनशीलता के साथ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवा कर हम टीबी की इस जंग को हर हाल में जीतेंगे।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा कि प्रदेशभर में 24 मार्च से 11,328 हाई रिस्क गांवों एवं वार्डों में विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। अभियान के अंतर्गत प्रदेश में अब तक करीब 5 हजार आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजित किए गए, जिनमें 18.93 लाख से अधिक व्यक्तियों की टीबी स्क्रीनिंग की गई। समय पर एवं सटीक जांच करने के लिए 16.51 लाख चेस्ट एक्स-रे तथा 1.41 लाख से अधिक एनएएटी जांचें सुनिश्चित की गईं।

उन्होंने बताया कि सक्रिय केस खोज (एक्टिव केस फाइंडिंग) गतिविधियों के माध्यम से अभियान के दौरान कुल 32,102 नए टीबी रोगियों की पहचान की गई। इनमें 10,457 ऐसे मरीज शामिल हैं, जिनमें किसी प्रकार के लक्षण नहीं थे। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि स्वास्थ्य विभाग की सक्रिय एवं वैज्ञानिक कार्यप्रणाली को दर्शाती है।

संवेदनशील एवं उच्च जोखिम वाली आबादी तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के उद्देश्य से अधिक से अधिक व्यक्तियों की एक्सरे एवं नाट मशीन से जांच की जा रही है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि गुणवत्तापूर्ण एवं आवश्यकता आधारित उपचार सुनिश्चित करने हेतु डिफरेंशिएटेड टीबी केयर के अंतर्गत 32 हजार से अधिक पात्र मरीजों में से 16 हजार 500 से अधिक मरीजों का आकलन किया गया, जो 51 प्रतिशत उपलब्धि है।

उड़ान योजना को तुरंत बहाल करे भाजपा सरकार : अशोक गहलोत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज 'मासिक धर्म स्वच्छता दिवस' के विशेष अवसर पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को एक पत्र लिखकर प्रदेश की बालिकाओं और महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े एक बेहद संवेदनशील और जरूरी विषय की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया है। गहलोत ने मांग की है कि राज्य में महिलाओं के स्वास्थ्य और मानवीय गरिमा से जुड़ी 'उड़ान योजना' के तहत निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन का वितरण तत्काल प्रभाव से पुनः प्रारंभ किया जाए।

पूर्व मुख्यमंत्री ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि मासिक धर्म स्वच्छता केवल एक स्वास्थ्य विषय नहीं, बल्कि महिलाओं की शिक्षा, आत्मसम्मान और सामाजिक भागीदारी से सीधे जुड़ा हुआ मूलभूत अधिकार है। जब किशोरियों और महिलाओं को स्वच्छ सेनेटरी उत्पाद उपलब्ध नहीं होते, तब वे न केवल शारीरिक कष्ट झेलती हैं, बल्कि सेनेटरी नैपकिन की अनुपलब्धता के कारण कपड़े, राख और मिट्टी जैसे असुरक्षित विकल्पों का उपयोग करने पर विवश हो जाती हैं। इससे गर्भाशय व प्रजनन संबंधी संक्रमण, मूत्र मार्ग संक्रमण एवं कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का जोखिम अत्यधिक बढ़ जाता है। इसके साथ ही, किशोरी बालिकाएं विद्यालय से अनुपस्थित रहने लगती हैं और माहवारी से जुड़ी शर्म व सामाजिक कलंक के कारण बीच में ही स्कूल छोड़ देती हैं, जिससे उनकी शैक्षणिक प्रगति और महिलाओं की आर्थिक उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

इस संदर्भ में ऐतिहासिक कानूनी पक्ष को रेखांकित करते हुए गहलोत ने याद दिलाया कि सर्वोच्च न्यायालय ने 30 जनवरी 2025 को एक ऐतिहासिक निर्णय में मासिक धर्म स्वच्छता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के मूल अधिकार का अभिन्न अंग घोषित किया है, जिसके तहत सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक की बालिकाओं को निःशुल्क बायोडिग्रेडेबल सेनेटरी नैपकिन अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराए जाने का आदेश है। उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल का संदर्भ देते हुए बताया कि वर्ष 2021 में प्रारंभ की गई 'आई एम शक्ति उड़ान योजना' के अंतर्गत राजस्थान की 10 से 45 वर्ष की समस्त बालिकाओं एवं महिलाओं को प्रतिमाह 12 निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन वितरित किए जाते थे, जिससे प्रदेश की लगभग 1 करोड़ 20 लाख महिलाएं लाभान्वित हो रही थीं।

अभिनंदन

उपमुख्यमंत्री एवं राजसमंद प्रभारी मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने गुरुवार को नाथद्वारा पहुंचकर प्रभु श्रीनाथजी के सपरिवार दर्शन किए। इस दौरान मंदिर मण्डल द्वारा परंपरागत रूप से उपमुख्यमंत्री का अभिनंदन किया गया। इस दौरान मंदिर मण्डल सीईओ जितेंद्र पांडे सहित अन्य मौजूद रहे।

जल संरक्षण हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी : जोगाराम पटेल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। वंदे गंगा जल संरक्षण ,जन अभियान के तहत जिला प्रशासन व जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र द्वारा सीएसआर कार्यशाला का आयोजन विधि, संसदीय एवं जयपुर जिले के प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल के मुख्य आतिथ्य में गुरुवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में हुआ। प्रभारी मंत्री ने कहा कि जल धरती के प्राणिमात्र की मूलभूत आवश्यकता है। जल है तो कल है ,जल है तो जीवन है। जल को भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी बताते हुए उन्होंने जिले के सभी उद्यमियों, किसानों, सामाजिक संगठनों, कार्मिकों एवं आमजन से जल संरक्षण के इस पुनीत कार्य में पूरे तन, मन व धन से जुड़कर इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देकर जयपुर जिले को जल संरक्षण के क्षेत्र में अग्रणी जिला बनाने का आह्वान किया। उन्होंने इस दौरान उपस्थित सभी लोगों को जल संरक्षण की शपथ भी दिलवाई।

कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे जिला कलेक्टर संदेश नायक ने प्राणिमात्र के लिए जल की महता बताते हुए सभी उद्यमियों से जल संरक्षण कार्यों में अधिक से अधिक धनराशि दान करने की अपील की। इस अवसर पर जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र के महाप्रबंधक सुभाष शर्मा ने अपने स्वागतीय भाषण में 25 मई से 5 जून 2026 तक संचालित इस अभियान में सभी उद्यमियों को व्यापक व सक्रियता से भाग लेने की अपील की। इस दौरान वरिष्ठ भूजल वैज्ञानिक डॉ मलेंद्र चौहान ने अधिक भूजल दोहन से उत्पन्न खतरे व जल ग्रहण विभाग के अधीक्षण अभियंता गोपाल प्रसाद जैन ने बारिश की एक-एक बूंद को सहेजने ने की महत्ता पर प्रस्तुति दी। पानी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध पर्यावरणविद पद्म लक्ष्मण सिंह लापोडिया वाले व धरती अमृत वाले पद्म सुण्डाराम व उद्यमियों ने जल संरक्षण,पौधारोपण व पर्यावरण संरक्षण के संबंध में उनके द्वारा किए गए कार्यों से सभी को अवगत कराया।

इस अवसर पर महाप्रबंधक जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र, जयपुर शहर डॉक्टर अनुकृति सिंह ने उद्यमियों और गो प्रतिनिधियों को कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान उपवन संरक्षक वी केतन कुमार,अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम विनीता सिंह, अतिरिक्त जिला कलेक्टर चतुर्थ आशीष कुमार सहित अन्य अधिकारी एवं जिले के उद्यमी व सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कंपनियों को जारी किए गए निर्देश

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राज्य सरकार किसान हित में प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है और उनकी आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। बदलते मौसम, ओलावृष्टि, चक्रवाती वर्षा एवं कटाई के बाद 14 दिन तक खेत में सूखने के लिए रखी फसल खराब होने पर किसानों को होने वाले नुकसान से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक मजबूत सुरक्षा कवच के रूप में कार्य कर रही है। कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने बताया कि फसल बीमा की गाइडलाइन के अनुसार फसल बीमा में बीमित किसी किसान की मृत्यु के बाद उनके वारिसों को बीमा राशि न्यायालय से उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र लाने पर ही देय थी। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करना जटिल प्रक्रिया होने के कारण कई बार बीमा क्लेम राशि कम होने के कारण किसान इसमें रुचि भी नहीं ले रहे थे।

फसल बीमा योजना के अंतर्गत दिवंगत बीमित कृषकों के लंबे समय से लंबित फसल बीमा दावों के त्वरित निस्तारण के लिए अधिसूचित बीमा कंपनियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। इस निर्णय से हजारों कृषक परिवारों को समय पर फसल बीमा क्लेम मिल सकेगा। राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर बीमित कृषक द्वारा किसी पारिवारिक सदस्य को मनोनीत किया गया है, तो बीमा दावा राशि का भुगतान तत्काल संबंधित मनोनीत सदस्य को किया जाएगा।

ऐसे मामलों में जहां मनोनयन उपलब्ध नहीं है, वहां दिवंगत कृषक के लंबित फसल बीमा दावों का भुगतान न्यायालय द्वारा जारी वैध उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, संबंधित तहसीलदार अथवा पटवारी द्वारा जारी वारिसनामा या परिवार के सभी सदस्यों की सहमति से अधिकृत किसी एक पारिवारिक सदस्य को किया जा सकेगा। गोयल ने बताया कि जिन प्रकरणों में कोई पारिवारिक विवाद नहीं है वहां उत्तराधिकार प्रमाण पत्र अथवा वारिसनामा की अनिवार्यता नहीं होगी। यदि परिवार के सभी सदस्य 50 रुपये के नोटरी स्टाम्प पर शपथ पत्र देकर किसी एक सदस्य को दावा राशि प्राप्त करने हेतु अधिकृत करते हैं, तो बीमा कंपनी उस अधिकृत सदस्य के बैंक खाते में सीधे भुगतान कर सकेगी।

सावरकर के आदर्शों से भारत महान और बिहार समृद्ध बनेगा : सम्राट चौधरी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

पटना/भाषा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बृहस्पतिवार को कहा कि विनायक दामोदर सावरकर के राष्ट्रवादी विचारों का अनुसरण कर भारत महान बनेगा और बिहार समृद्धि हासिल करेगा।

बिहार विधान परिषद परिसर में सावरकर की 143वीं जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में उनकी जीवनी पर आधारित पुस्तक 'वीर सावरकर की जीवनी' के विमोचन के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सावरकर पर शोध को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि युवा उनसे प्रेरणा ले सकें।

चौधरी ने कहा कि ब्रिटिश शासकों और कुछ भारतीय इतिहासकारों के प्रयासों के बावजूद आज भारत का हर नागरिक और बच्चा सावरकर के व्यक्तित्व, कार्यों और देशभक्ति से परिचित है। उन्होंने कहा कि सावरकर ने ब्रिटिश शासन के दौरान लगभग 27 वर्ष कारावास में बिताए और भीषण यातनाएं सहीं, जिन्हें इतिहासकारों ने उनके साथियों की तुलना में सबसे अधिक कष्टपूर्ण माना है। चौधरी ने आरोप लगाया कि देश को ब्रिटिश शासन से छुटकारा मिलने के बाद भी स्वतंत्रता के शुरुआती 20 वर्षों में लोग परेशान रहे, जिसके बाद आपातकाल लागू किया गया। उन्होंने कहा, लोगों ने कांग्रेस और आपातकाल के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की। जनसंघ ने पार्टी से पहले राष्ट्र को प्राथमिकता दी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का भी स्पष्ट दृष्टिकोण है कि पहले राष्ट्र की रक्षा होनी चाहिए और उसके बाद पार्टी। सावरकर इसी विचारधारा के प्रतीक थे। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सावरकर की विचारधारा से प्रेरित होकर राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगातार जुटे हुए हैं।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस्कॉन मुख्यालय का दौरा किया, 'गौ पूजा' की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोलकाता/भाषा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बृहस्पतिवार को नदिया जिला स्थित इस्कॉन मुख्यालय पहुंचे और 'गौ पूजा' की। राजनीतिक एवं आध्यात्मिक रूप से उनका यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उन्होंने इस्कॉन के साधु-संतों और मंदिर प्रबंधन के सदस्यों से भी बात की।

अधिकारियों के अनुसार, पारंपरिक सफेद धोती-कुर्ता पहने शुभेंदु पूर्वाह्न करीब साढ़े 11 बजे नंगे पांव मंदिर परिसर की गौशाला में दाखिल हुए, और विशेष 'गौ पूजा' अनुष्ठान किया तथा बाद में गायों को फल व मिठाइयां खिलाईं। वह 'यज्ञ' में शामिल हुए और फिर इस्कॉन के साधु-संतों तथा प्रबंधन के सदस्यों से बात करने के लिए चंद्रोदय मंदिर पहुंचे। विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद इस महीने की शुरुआत में मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभालने के बाद शुभेंदु का मायापुर स्थित इस्कॉन मुख्यालय का यह पहला दौरा है। मुख्यमंत्री के मायापुर पहुंचते ही कीर्तन की मधुर ध्वनि के बीच साधु-संतों और श्रद्धालुओं ने उनका स्वागत किया। सैकड़ों लोग सुबह से ही मंदिर परिसर के आसपास उनकी एक झलक पाने के लिए एकत्र थे। इस दौरान मंदिर नगरी में उत्सव जैसा माहौल था।

अधिकारियों ने बताया कि मायापुर और इसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए, प्रमुख प्रवेश द्वारों पर अवरोधक लगाए गए और मंदिर परिसर के कुछ हिस्सों में आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस्कॉन के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने संगठन और इसके कार्यों के प्रति गहरी रुचि और उत्साह'' दिखाया। प्रवक्ता ने कहा, ''मुख्यमंत्री बनने के बाद यह पहली बार है जब वह इस्कॉन मायापुर आए हैं। उन्होंने 'गोपी-जन गौ सेवा' और यज्ञ अनुष्ठानों में भाग लिया। साधु-संतों के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया जाएगा।''

यद्यपि, इसे आध्यात्मिक दौरे के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन इस दौरे का स्पष्ट रूप से राजनीतिक निहितार्थ है, विशेषकर ऐसे राज्य में जहां धर्म और सांस्कृतिक पहचान से जुड़े प्रतीकों का चुनावी महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों ने रेखांकित किया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विधानसभा चुनाव से पहले फरवरी में इस्कॉन मुख्यालय का दौरा किया था, और इस दौरान अधिकारी शुभेंदु भी उनके साथ थे।

सशस्त्र समूहों द्वारा बंधक बनाए गए लोगों का पता लगाने के लिए खोजबीन अभियान जारी : युमनाम खेमचंद सिंह

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

इंफाल/भाषा। मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने बृहस्पतिवार को कहा कि सुरक्षा बल सशस्त्र समूहों द्वारा बंधक बनाए गए लोगों का पता लगाने के लिए इलाके में खोजबीन अभियान चला रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कांगपोकपी जिले के माखन नगा गांव के दौरे के दौरान पत्रकारों को बताया कि छह नगा लोगों के अपहरण में शामिल होने के संदेह में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है और बंधकों का पता लगाने के लिए खोजबीन अभियान जारी है। कांगपोकपी और सेनापति जिलों में 13 मई को सशस्त्र समूहों द्वारा 38 से अधिक लोगों का अपहरण करके उन्हें बंधक बना लिया गया। यह घटना कांगपोकपी जिले में एक घात लगाकर किए गए हमले में तीन चर्च के पदाधिकारियों की हत्या के कुछ घंटों बाद हुई। इनमें से 31 लोगों को रिहा कर दिया गया है, जिनमें 12 नगा महिलाएं और 16 कुकी शामिल हैं। हालांकि, छह नगा पुरुष अब भी बंधक बनाकर रखे गए हैं और उनके ठिकाने का अब तक पता नहीं चल पाया है। मणिपुर राज्य में कुकी जनजातियों की सर्वोच्च संस्था 'कुकी इनपी मणिपुर' ने दावा किया कि समुदाय के 14 लोग अब भी नगा समूहों द्वारा बंधक बनाकर रखे गए हैं। सिंह ने कहा कि दोषियों को पकड़ने के लिए जांच जारी है। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि बंधकों का जल्द ही पता लगा लिया जाएगा। कांगपोकपी जिले के माखन नगा गांव में आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के लिए एक राहत शिविर भी है। सिंह ने माखन बैपटिस्ट चर्च में शरण लिए हुए लोगों से मुलाकात की और राहत सामग्री वितरित की। ग्राम प्रधान ने मुख्यमंत्री को बताया कि कांगपोकपी जिले में कई नगा लोग डर के कारण अपने गांव छोड़कर चले गए हैं।

राहुल गांधी ओबीसी अधिकारों की बात तो करते हैं, लेकिन ओबीसी नेताओं को आगे नहीं बढ़ाते: भाजपा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। भाजपा ने बृहस्पतिवार को ओबीसी प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला करते हुए उन्हें ''पाखंडी'' बताया और कहा कि वह जाति जनगणना तथा ओबीसी अधिकारों की बात तो करते हैं, लेकिन ओबीसी नेताओं को उच्च पदों पर पदोन्नत नहीं करते।

यह टिप्पणी सिद्दरामय्या के कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने और डी के शिवकुमार के इस भूमिका को संभालने की संभावना के बीच आई है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने वीडियो संदेश में दावा किया कि वी डी सतीशन, सुखविंदर सिंह सुक्खू और रेवंत रेड्डी सहित कई कांग्रेस नेता ओबीसी समुदाय से संबंधित नहीं हैं। पूनावाला ने कहा, ''राहुल गांधी ने कहा है कि अधिकार जनसंख्या के अनुपात में होने चाहिए और उन्होंने जातिगत मुद्दों पर बार-बार चर्चा की है। हालांकि, उनके सिद्धांत हाथी के दांतों की तरह हैं - खाने के और, दिखाने के और। वह पाखंडी हैं, कहते कुछ हैं तथा करते कुछ और हैं।'' उन्होंने कहा कि शिवकुमार के सिद्दरामय्या की जगह लेने का मतलब है कि कांग्रेस शासित राज्यों में ''कोई ओबीसी मुख्यमंत्री नहीं होगा''। पूनावाला ने पूछा, ''केरल में सतीशन जी; हिमाचल प्रदेश में सुक्खू जी; तेलंगाना में रेवंत रेड्डी जी (मुख्यमंत्री हैं); और कर्नाटक में आपने सिद्दरामय्या जी को हटा दिया है। तो फिर ओबीसी प्रतिनिधित्व कहां है?'' उन्होंने आरोप लगाया कि जाति को लेकर कांग्रेस पार्टी के सिद्धांतों और व्यवहारिकता में कोई तालमेल नहीं है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा, ''यह प्रथम परिवार के आरजीएफ ट्रस्ट या कांग्रेस कार्य समिति में भी नहीं दिखता। इसके विपरीत, भाजपा ने एक ओबीसी नेता को प्रधानमंत्री बनाया है, जो वर्तमान में अपना तीसरा कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। यह कांग्रेस और भाजपा के बीच के अंतर को उजागर करता है।'' कांग्रेस पर पिछड़े वर्ग के नेताओं को निशाना बनाने का आरोप लगाते हुए पूनावाला ने कहा कि पार्टी ''केवल विभाजन पैदा करने की कोशिश करती है लेकिन कभी अपनी कथनी और करनी में समानता नहीं रखती'', तथा उसने सीताराम केसरी और बी आर अंबेडकर जैसे नेताओं का भी अपमान किया था।

अदालत ने असम के मुख्यमंत्री को 'मिया मुसलमानों' संबंधी टिप्पणी पर नोटिस जारी किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। दिल्ली की एक अदालत ने 'मिया मुसलमानों' संबंधी टिप्पणी को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा को नोटिस जारी किया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनू अग्निहोत्री ने कार्यकर्ता हर्ष मंदर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए शर्मा को नोटिस जारी किया। यह याचिका मजिस्ट्रेट अदालत के 20 अप्रैल के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें भाजपा नेता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देने से इनकार कर दिया गया था। अदालत ने 26 मई के अपने आदेश में कहा, याचिकाकर्ता के वकील ने याचिकाकर्ता की पुनर्विचार याचिका के साथ शून्य प्राथमिकी और ई-प्राथमिकी के लिए प्रस्तुत गृह मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की ओर मेरा ध्यान आकृष्ट किया। याचिकाकर्ता के वकील द्वारा प्रस्तुत दलीलों के मद्देनजर, प्रतिवादियों को पुनर्विचार याचिका का नोटिस जारी किया जाए और उन्हें 15 जुलाई, 2026 तक उचित जवाब दाखिल करने को कहा जाए। मंदर ने असम के तिनसुकिया जिले के डिगबोई में एक कार्यक्रम के दौरान 27 जनवरी को कथित तौर पर भड़काऊ बयान देने के मामले में अप्रैल में शर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आग्रह करते हुए आवेदन दायर किया था। याचिका के अनुसार, शर्मा ने कथित तौर पर कहा था कि असम में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान ''चार से पांच लाख मिया मतदाताओं'' का नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा। असम में बांग्ला भाषी मुसलमानों के लिए 'मिया' एक अपमानजनक शब्द है, और गैर-बांग्ला भाषी लोग आमतौर पर उन्हें बांग्लादेशी मानते हैं। मंदर ने अपने आवेदन में यह भी दावा किया कि असम के मुख्यमंत्री ने कथित तौर पर यह कहकर 'मिया' समुदाय के खिलाफ लोगों को भड़काया कि ''वे तभी असम छोड़ेंगे जब उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा'' और ''हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि वे असम में मतदान न कर सकें''।

त्रिपुरा में निवेश आकर्षित करने में मदद करेंगे प्रधानमंत्री मोदी: मुख्यमंत्री माणिक साहा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

अगरतला/भाषा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्य में निवेश आकर्षित करने और उद्योगों एवं संबद्ध क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए समर्थन का आश्वासन दिया है। राज्य सरकार ने लगभग 30,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने के लिए जुलाई में एक व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया है।

साहा ने पत्रकारों से कहा, मैंने 26 मई को प्रधानमंत्री के साथ विकास से लेकर वित्तीय मामलों और व्यापार सुगमता के लिए उदारीकरण उपायों जैसे विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। पहले चरण में, त्रिपुरा उदारीकरण के कार्यान्वयन में प्रथम स्थान पर रहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सीमावर्ती राज्य में निवेश लाने और उद्योगों एवं संबद्ध क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए समर्थन का आश्वासन दिया है।

साहा ने बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया से भी मुलाकात की।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा, राज्य शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों पर प्रधान के साथ सार्थक चर्चा हुई। उन्होंने 'फेसबुक' पर कहा, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, आधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास, डिजिटल शिक्षा के विस्तार और विद्यार्थियों के लिए बेहतर सुविधाओं व अवसरों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई।

राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान पर पलटवार करते हुए कहा-

मुझ पर हमला करने से आपके अपराध कम नहीं होंगे

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नीट-सीबीएसई मुद्दे पर धर्मेंद्र प्रधान की टिप्पणियों पर पलटवार करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि उन पर हमला करने से शिक्षा मंत्री के अपराध कम नहीं होंगे। प्रधान ने इससे पहले गांधी पर इस मामले का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि कांग्रेस नेता 'हताश' और भारत की 'तकनीकी प्रगति के विरोधी' हैं।

गांधी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''धर्मेंद्र प्रधान जी, आप मुझ पर जितने चाहे हमले कर लें, लेकिन इससे आपके अपराध कम नहीं होंगे। न ही इससे मुझे 18.5 लाख बच्चों के लिए जवाब मांगने से रोका जा सकेगा।'' गांधी ने कई सवाल उठाते हुए पूछा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ओएसएम का अनुबंध 'सीओईएमपीटी' को क्यों दिया गया - ''एक ऐसी कंपनी जो अपने पुराने नाम, ग्लोबरीना के तहत पहले से ही विवादों में घिरी हुई है?'' लोकसभा में विपक्ष के नेता ने पूछा, ''ऐसा किसके आदेश पर किया गया? कंपनी की पृष्ठभूमि की जांच क्यों नहीं की गई? 'सीओईएमपीटी' के प्रबंधन और मोदी सरकार के बीच क्या संबंध है?'' उन्होंने कहा, ''या तो आपने पृष्ठभूमि की जांच कराई और फिर भी आगे बढ़ गए - या आपने बिल्कुल भी पृष्ठभूमि की जांच नहीं कराई। दोनों ही मामलों में, आप दोषी हैं।'' गांधी ने कहा कि यदि प्रधानमंत्री को वाकई स्थिति की परवाह होती, तो उन्हें असंख्य विद्यार्थियों के भविष्य को खतरे में डालने के लिए प्रधान को बहुत पहले ही बर्खास्त कर देना चाहिए था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''लाखों भारतीय विद्यार्थियों के लिए उन्होंने जो अराजकता पैदा की है और मंत्री के रूप में जो घोर अक्षमता दिखाई है, इसके बावजूद भी अहंकार और राजनीतिक नाटकबाजी ही प्रधान के पास सबसे अच्छा जवाब है।'' रमेश ने कहा कि प्रधान अब विपक्ष के नेता को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि वह शिक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति की आलोचना करने से संतुष्ट नहीं हैं।

मथुरा में ईद की नमाज के बाद दो पक्षों में हिंसक झड़प, एक व्यक्ति की मौत

मथुरा/भाषा। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में ईद की नमाज के बाद बच्चों के बीच हुए मामूली विवाद ने वयस्कों के दो समूहों के बीच हिंसक झड़प का रूप ले लिया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

यह घटना कोसीकलां थाना क्षेत्र के नगला मेव गांव में हुई।

थाना प्रभारी कमलेश सिंह ने बताया कि आशु और नवाब नामक दो व्यक्तियों के बच्चे मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद घर लौट रहे थे, तभी किसी बात को लेकर उनकी इदरिस के बच्चों से कहासुनी हो गई। उन्होंने बताया कि घर पहुंचने पर बच्चों ने कथित मारपीट की जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए।

थाना प्रभारी के अनुसार, शुरुआती कहासुनी जल्द ही हिंसक झड़प में बदल गई और दोनों पक्षों के लोगों ने एक-दूसरे पर लाठियों से हमला कर दिया। कुछ ग्रामीणों ने बीच-बचाव की कोशिश भी की।

इस दौरान नवाब (35) गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

मनीष तिवारी की टिप्पणी के बाद भाजपा ने कहा- कांग्रेस में योग्य लोगों के लिए कोई जगह नहीं

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बी एल संतोष ने कहा कि कांग्रेस में ''योग्य व्यक्तियों'' के लिए कोई जगह नहीं है। उनकी यह टिप्पणी तब आई जब कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सरदार केवल सिंह ढिल्लों को भाजपा की पंजाब इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की आलोचना की। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने ढिल्लों को पार्टी की पंजाब इकाई का प्रमुख नियुक्त किया।

बरनाला से दो बार कांग्रेस के विधायक रह चुके ढिल्लों 2022 में भाजपा में शामिल हो गए थे और बाद में उन्हें पार्टी की प्रदेश इकाई का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तिवारी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में, ढिल्लों की भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को लेकर निशाना साधा और कहा, ''पंजाब में भाजपा की स्थिति पर यह एक स्पष्ट टिप्पणी है कि वह प्रदेश अध्यक्षों के रूप में नियुक्त करने के लिए केवल पूर्व कांग्रेसी नेताओं को ही ढूंढ़ पा रही है।'' कांग्रेस सांसद की टिप्पणी पर संतोष ने पलटवार करते हुए 'एक्स' पर लिखा, ''और यह एक सर्वविदित तथ्य है कि कांग्रेस में योग्य व्यक्तियों के लिए कोई जगह नहीं है।'' भाजपा की पंजाब इकाई के नवनियुक्त अध्यक्ष ढिल्लों को पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का करीबी माना जाता है, जो कांग्रेस से अलगाव के लगभग एक साल बाद 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे।

एटा में भागवत कथा कार्यक्रम के दौरान हर्ष फायरिंग, दो गिरफ्तार

एटा/भाषा। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में भागवत कथा कार्यक्रम के दौरान 'हर्ष फायरिंग' करने के आरोप में पुलिस ने बृहस्पतिवार को दो लोगों को गिरफ्तार कर उनके लाइसेंसी हथियार जब्त कर लिए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार, बुधवार को भागवत कथा पंडाल में हुई हर्ष फायरिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसके बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रघुराज सिंह (45) और भूरी सिंह (50) के रूप में हुई है, जो कुसवा गांव के निवासी हैं। दोनों के पास से एक लाइसेंसी राइफल और एक लाइसेंसी डबल बैरल बंदूक (डीबीबीएल) बरामद की गई है, जिनका उपयोग कथित तौर पर फायरिंग में किया गया था। रघुराज सिंह के खिलाफ पहले भी मारपीट और आपराधिक धमकी के मामले दर्ज हैं, जबकि भूरी सिंह के खिलाफ वर्तमान मामले में कार्रवाई की जा रही है।

ऑलराउंडर दुबे ने पहली बार भारतीय टीम में चुने जाने पर कहा- किसी की जगह लेने की कोशिश नहीं कर रहा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नागपुर/भाषा। युवा स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर हर्ष दुबे भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी खुद की पहचान बनाना चाहते हैं और किसी अनुभवी सीनियर क्रिकेटर के 'विकल्प' के तौर पर नहीं पहचाने जाना चाहते।

बाएं हाथ के स्पिनरों और बाएं हाथ के बल्लेबाजों की सूची में सबसे होनहार ऑलराउंडरों में से एक विदर्भ के 23 वर्षीय क्रिकेटर दुबे को अगले महीने अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले एकमात्र टेस्ट और तीन मैच की एकदिवसीय शृंखला के लिए पहली बार भारतीय टीम में जगह मिली है।

राष्ट्रीय चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर ने संकेत दिया कि वे दुबे को भविष्य की संभावना के तौर पर देख रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को अफगानिस्तान के खिलाफ इस टेस्ट मैच के लिए सिर्फ आराम दिया गया है। सनराइजर्स हैदराबाद के साथ आईपीएल सत्र पूरा करने के बाद नागपुर पहुंचने पर दुबे ने पीटीआई से कहा, ''इस मौके ने

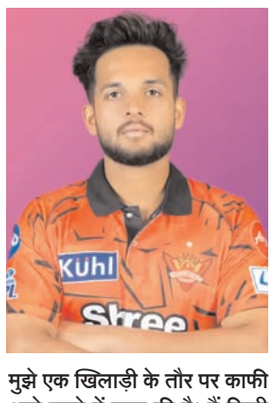

मुझे एक खिलाड़ी के तौर पर काफी आगे बढ़ने में मदद की है। मैं किसी की जगह लेने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैंने इस मौके के लिए कड़ी मेहनत की है और मेरी यही मेहनत आज मुझे यहां तक लाई है। भविष्य के बारे में बहुत अधिक सोचने की जगह मेरा पूरा ध्यान इस बात पर है कि मुझे जब भी मौका मिले तो मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूं।''

तीनों प्रारूप में 95 मुकाबलों में अब तक 198 विकेट ले चुके दुबे खुद पर बेवजह का दबाव नहीं डालना चाहते, विशेषकर अगर उन्हें छह जून से मुल्लांपुर में होने होने वाले एकमात्र टेस्ट मैच की एकादश में जगह मिलती है तो। दुबे ने कहा, ''अभी मैं इस अंतरराष्ट्रीय मैच को किसी भी अन्य मैच की तरह ही ले रहा हूं। मैं खुद पर बहुत अधिक दबाव नहीं डालना चाहता। मैं बस अपनी काबिलियत पर भरोसा रखना चाहता हूं और वही करते रहना चाहता हूं जो मेरे लिए हमेशा कारगर रहा है।'' बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी दुबे की मुख्य ताकत है जिससे उन्होंने 133 प्रथम श्रेणी विकेट लिए हैं (जिनमें नौ बार पारी में पांच या इससे अधिक विकेट और दो बार मैच में 10 या इससे अधिक विकेट लेने का कारनामा शामिल है) लेकिन दुबे बल्लेबाजी में भी माहिर हैं और अब तक 27 प्रथम श्रेणी मुकाबलों में 1000 से अधिक रन बना चुके हैं।

खेल प्रशासन मुश्किल है, लेकिन व्यवस्था को साफ करना जरूरी है: पूरव राजा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। पूर्व युगल टेनिस खिलाड़ी पूरव राजा का कहना है कि भारतीय टेनिस प्रशासन में निचले स्तर से जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ पूरी तरह से सुधार की जरूरत है, हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि खेल प्रशासन इतना कठिन क्षेत्र है कि उन्हें खुद नहीं लगता कि उनके पास इसे संभालने की काबिलियत है।

राजा और पूर्व डेविस कप खिलाड़ी सोमदेव देववर्मन ने 2024 में अखिल भारतीय टेनिस संघ (एआईटीए) के चुनावों को चुनौती दी थी जिसके बाद पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल को प्रशासक नियुक्त किया गया, ताकि संघ के कामकाज की निगरानी की जा सके और राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के अनुरूप उसके संविधान को तैयार कर नए चुनाव कराए जा सकें। राजा ने पीटीआई से कहा, ''व्यवस्था को पेशेवर तरीके से चलाया जाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि मैं इसके लिए कितना काबिल हूं। खेल प्रशासन एक बहुत कठिन क्षेत्र है।'' उन्होंने कहा, ''हमने यह याचिका इसलिए दायर नहीं की थी कि हम एआईटीए को अपने हाथ में लेना चाहते थे। जो भी शीर्ष पद संभाल रहा हो, उसका चुनाव निष्पक्ष और संवैधानिक तरीके से होना चाहिए। मेरा योगदान यह है कि पहली बार हमने किसी को निगरानी और नियमों में सुधार के लिए लाने में सफलता पाई। ''राजा ने हालांकि यह भी कहा कि भारतीय टेनिस प्रशासन में संरचनात्मक समस्याएं गहरी जड़ें जमा चुकी हैं जो जिला स्तर से शुरू होती हैं और पूरी व्यवस्था के वित्तीय रूप से सफाई की जरूरत है।

सुविचार

इज्जत और तारीफ माँगी नहीं जाती, कमाई जाती है, नेकी का रास्ता कठिन है, पर अंत सुखद होता है।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

यह आग नहीं, अमृत बरस रहा है

आजकल अख़बारों, टीवी, यूट्यूब चैनलों, फ़ेसबुक, एक्स ... सब जगह एक ही ख़बर चल रही है– 'आसमान से बरस रही आग ... भारत में पड़ रही भयंकर गर्मी ... हर कोई परेशान ... दूर–दूर तक राहत के आसार नहीं।' कुछ दिन बाद जब मानसून आ जाएगा तो सब जगह यह ख़बर दिखाई देगी– 'नदी–नाले उफान पर ... सड़कें बनीं दरिया ... सड़कों पर सैलाब।' ऐसा हर साल पढ़ने–सुनने को मिलता है। कल जो विपक्ष में थे, वे यह स्थिति देखकर शिकायत करते थे। आज जो विपक्ष में हैं, वे शिकायत करते हैं। भविष्य में जो विपक्ष में होंगे, वे भी शिकायत करेंगे। समस्या सब जानते हैं। समाधान की बात उस स्तर पर नहीं हो रही है। ऐसा लगता है कि अब हम कृषि प्रधान समाज नहीं रहे, बल्कि शिकायत प्रधान समाज बन गए हैं। हर कहीं शिकायतों का शोर है। समाधान की चर्चा कम ही सुनाई दे रही है। अगर अभी आसमान से आग बरस रही है तो इसका सही–सही उपयोग करें, ताकि यह ईंधन की जगह काम आए। आग अपनेआप में बहुत बड़ी शक्ति होती है। दुनिया इसके लिए डॉलर वसूलती है। ईश्वर हमें यह मुफ्त में दे रहे हैं। अगर हम अपना नज़रिया थोड़ा–सा बदलें, कुछ सावधानी भी रखें तो पाएंगे कि आसमान से आग नहीं बरस रही, बल्कि अमृत बरस रहा है। हमने अपने अंदर वह शक्ति और सामर्थ्य पैदा नहीं की, जिससे इसका पर्याप्त मात्रा में सदुपयोग कर सकें। जब वर्ष 1767 में जिनेवा के वैज्ञानिक होरेस–बेनेडिक्ट डी सॉसर ने एक 'हॉट बॉक्स' या शुरुआती 'सोलर ओवन' बनाकर उसके सिद्धांतों का वर्णन किया था तो कई लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि सूरज की रोशनी से खाना पकाया जा सकता है। इसके लगभग सौ साल बाद फ्रेंच फॉरेन लीजन (फ्रेंच सेना की एक विशिष्ट शाखा) ने सूरज की रोशनी से खाना पकाने के सिद्धांत को काफी हद तक विकसित कर लिया था। हालांकि तब भी यह एक उपेक्षित आविष्कार था, जो आज तक है।

यूरोप में संभवत: ठंड की अधिकता के कारण इस आविष्कार को बहुत बढ़ावा नहीं मिला, लेकिन भारत में ऐसी कोई समस्या नहीं है। यहां खूब धूप पड़ती है। ज्यादातर इलाके प्रकृति के इस वरदान से मालामाल रहते हैं। अगर भारत में शिकायतों के बजाय सोलर कुकर या सोलर ओवन के उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाता तो आज कहीं ईंधन की कोई समस्या नहीं होती। इसमें भारी पुर्जे नहीं लगते। तेल, गैस और लकड़ी का कोई झंझट नहीं है। भारत में एक औसत परिवार साल में लगभग छह से नौ एलपीजी सिलेंडर काम में लेता है। अगर वह नियमित रूप से सोलर कुकर का उपयोग करे, खासकर चावल, दाल, आलू और अन्य सब्जियां इसमें उबाले, पानी–दूध गर्म करे, तो लगभग 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक एलपीजी की बचत हो सकती है। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्य जहां साल में 250 से 300 दिन अच्छी धूप होती है, वहां सोलर कुकर का अनुशासित उपयोग इससे भी ज्यादा एलपीजी की बचत करवा सकता है। अगर समस्त देशवासी दृढ़ निश्चय कर लें तो हम सालाना करोड़ों सिलेंडर बचा सकते हैं! इससे विदेशी मुद्रा भंडार के अरबों डॉलर की बचत हो सकती है। सिर्फ दर्पण, धूप, वैज्ञानिक सोच और दृढ़ निश्चय के दम पर हम भारतवासी दुनिया के सामने एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। ध्यान रखें, सोलर कुकर एलपीजी सिलेंडर का पूर्णत: स्थान नहीं ले सकता, लेकिन इसका अनुशासित उपयोग ईंधन की अच्छी–खासी बचत करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकता है। सरकार को चाहिए कि वह सोलर कुकर के बेहतर संस्करण तैयार करने के लिए वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन दे। इस क्षेत्र में अपार संभावना है। सोलर कुकर, एलपीजी और इलेक्ट्रिक कुकिंग के संयुक्त (हाइब्रिड) उपयोग से भविष्य में खाना पकाने का तरीका ज्यादा किफायती, टिकाऊ और पर्यावरण–अनुकूल बन सकता है।

ट्वीटर टॉक

मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे के मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एक लेटर लिखकर उड़ान स्कीम के तहत फ्री सैनिटरी नैपकिन बांटने का काम तुरंत फिर से शुरू करने की मांग की गई है। सैनिटरी नैपकिन न मिलने की वजह से लड़कियों को असुरक्षित ऑप्शन इस्तेमाल करने पड़ते हैं।

–अशोक गहलोत

राजस्थान सरकार अपनी 'ज़ीरो टॉलरेंस' पॉलिसी के तहत साइबर क्राइम के खिलाफ लगातार सख्त और असरदार एक्शन ले रही है।मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एक मज़बूत सिक्योरिटी सिस्टम के ज़रिए, हमारी सरकार हर नागरिक को एक सुरक्षित माहौल देने के लिए कमिटेड है।

–भजनलाल शर्मा

रिंचेनपोंग, जो अपने शानदार हिमालयी नज़ारों और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है, पश्चिम सिक्किम का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र है। यह इलाका आध्यात्मिकता और प्रकृति का खूबसूरती से मेल खाता है, जिसमें शानदार पहाड़ी नज़ारे शामिल हैं।

–गजेन्द्रसिंह शेखावत

प्रेरक प्रसंग

हल्का होने में सुकून

बा कमरुद्दीन नाम के पास एक अमीर सौदागर आया और बोला, 'बाबा, मेरे पास दौलत, हवेलियां और नौकर सब कुछ है, लेकिन दिल बेचैन रहता है। सुकून कहां मिलेगा?' फ़क़ीर ने उसे पत्थरों से भरा एक भारी बोरा दिया और कहा, 'इसे कंधे पर रखो और मेरे साथ चलो।' धूप तेज़ होती गई, रेत तपने लगी और कुछ दूर चलने के बाद सौदागर हांफने लगा। उसने कहा, 'बाबा, यह बोझ बहुत भारी है।' फ़क़ीर ने शांत स्वर में कहा, 'थोड़ा और चलो।'

थोड़ी देर बाद सौदागर गिर पड़ा और बोला, 'अब नहीं चला जाता!' तब फ़क़ीर ने कहा, 'बोरा नीचे रख दो।' जैसे ही उसने बोरा उतारा, उसे लगा मानो उसका शरीर हल्का हो गया हो। फ़क़ीर उसकी ओर देखकर बोले, 'जिस तरह यह बोरा तुझे थका रहा था, उसी तरह तेरी लालच, डर, घमंड और पुरानी शिकायतें तेरी रूह पर रखे पत्थर हैं।' फ़क़ीर ने मुट्ठी भर रेत उठाई और कहा, 'इंसान मुट्ठी बंद रखता है इसलिए दुखी रहता है। खोल दे, तो रेत भी गिर जाती है और हाथ भी हल्का हो जाता है।'

सामयिक

अब बख्शे नहीं जाएंगे घुसपैठिए

प्रमोद भार्गव

मो. 09425488224

नक्सल समस्या की तरह अब घुसपैठियों की समस्या का निदान भी होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी द्वारा घुसपैठियों को देष से बाहर करने की मुहिम से तय है कि देश का जनसंख्यात्मक घनत्व बिगाड़ रहे और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा बने इन बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिमों की विदाई तय है। अधिकारी ने बंगाल में भाजपा की जीत के साथ ही, सबका विकास, सबका साथ नारे को बदलते हुए तय कर दिया है कि जिसका साथ, उसका विकास किया जाएगा। घुसपैठियों के बंगाल में बसने और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री रहते हुए मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति के तहत मिल रहा था। किंतु अधिकारी ने 'डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट' नीति लागू करने और जिला स्तर पर होल्डिंग सेंटर बनाने का निर्णय लेकर जता दिया है कि आखिरकार अवैध प्रवासियों को बाहर जाना ही होगा। इसी कड़ी में गृहमंत्री अमित शाह ने प्लेटफार्म एक्स पर ऐलान कर दिया कि 'घुसपैठ और अप्राकृतिक जनसांख्यिकीय परिवर्तन किसी भी राष्ट्र के लिए वर्तमान और भविष्य के लिए बड़ी चुनौती है। इससे निपटने के लिए 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आबादी का संतुलन बिगड़ने की जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने की बात कही थी, जो अब कर दी गई है। यह समिति धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या बदलाव के तरीके की जांच व समीक्षा करेगी।' यह समिति सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता में काम कर एक साल के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।

बांग्लादेश के साथ भारत की कुल 4097 किलोमीटर लंबी सीमा-पट्टी है, जिस पर जरूरत के मुताबिक सुरक्षा के इंतजाम नहीं हैं। इस कारण गरीबी और भुखमरी के मारे बांग्लादेशी असम और बंगाल में घुसे चले आते हैं। क्योंकि यहां इन्हें कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल अपने-अपने वोट बैंक बनाने के लालच में भारतीय नागरिकता का सुगम आधार उपलब्ध करा देते हैं। मतदाता पहचान पत्र जहां इन्हें भारतीय नागरिकता का सम्मान हासिल करा देता है ।

बंगाल, असम और पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानीय बनाम विदेशी नागरिकों का मसला एक बड़ी समस्या बन गया है। जो यहां के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन को लंबे समय से झकझोर रहा है। बड़ी संख्या में घुसपैठ करके आए मुस्लिमों ने उनके न केवल आजीविका के संसाधनों को हथिया लिया है, बल्कि कृषि भूमि पर भी काबिज हो गए हैं। इस कारण राज्यों का जनसंख्यात्मक घनत्व बिगड़ रहा है। लिहाजा यहां के मूल निवासी और घुसपैठियों के बीच जानलेवा हिंसक झड़पें भी होती रहती हैं। नतीजतन अवैध और स्थाई नागरिकों की पहचान के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर एनआरसी यानी राष्ट्रीय नागरिकता पत्रक बनाने की पहल की थी। इस निर्देश के मुताबिक 1971 से पहले असम में रह रहे लोगों को मूल नागरिक माना गया है। इसके बाद के लोगों को अवैध नागरिकों की सूची में दर्ज किया गया है। दरअसल घुसपैठिए अपनी नागरिकता सिद्ध नहीं कर पाते हैं, तो यह उन राजनीतिक दलों को वजूद बचाए रखने की दृष्टि से खतरे की घंटी है, जो मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करते हुए घुसपैठ को बढ़ावा देकर अवैध नागरिकता को वैधता देने के उपाय करते रहे हैं। पहले सीपीएम और बाद में तृणमूल इन घुसपैठियों को न केवल शरण देते रहे हैं, बल्कि उनके आधार, राशन और वोटर कार्ड भी बनवाते रहे हैं। नतीजा रहा कि बंगाल का हर चौथा वोटर मुस्लिम बताया जा रहा है। छह जिले तो ऐसे हैं, जहां मुस्लिमों की आबादी 66 प्रतिशत से भी अधिक हैं। इस कड़ी में मुर्शिदाबाद जिले में 66.27, मालदा में 51.27, उत्तर दिनाजपुर 49.92, वीरभूमि में 37.06, दक्षिण 24 परगना 35.57 और नादिया में 26.27 प्रतिशत मुस्लिमों की आबादी हो गई है। सात ऐसे जिले हैं, जिनमें 12 प्रतिशत से लेकर 35 प्रतिशत तक आबादी है। इस बिगड़े जनसंख्यात्मक घनत्व का ही परिणाम रहा कि 34 साल सीपीएम और 15 साल तृणमूल ने बंगाल पर शासन करते हुए घुसपैठियों को संरक्षण देते रहे।

यदि असम में अवैध घुसपैठ की बात करें तो 1951 से 1971 के बीच यहां में मतदाताओं की संख्या अचानक 51 प्रतिशत बढ़ गई। 1971 से 1991 के बीच यह संख्या बढ़कर 89 फीसदी हो गई। 1991 से 2011 के बीच मतदाताओं की तादाद 53 प्रतिशत बढ़ी। 2001 की जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से यह भी देखने में आया कि असम में हिंदू आबादी तेजी से घटी और मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी 2011 की जनगणना में मुस्लिमों की आबादी और तेजी से बढ़ी। 2001 में जहां यह बढ़ोत्तरी 30.9 प्रतिषत थी, वहीं 2011 में बढ़कर 34.2 प्रतिशत हो गई। जबकि देश के अन्य हिस्सों में मुस्लिमों की आबादी में बढ़ोत्तरी 13.4 प्रतिशत से 14.2 फीसदी तक ही हुई। असम में 35 प्रतिशत से अधिक मुस्लिमों वाली 2001 में विधानसभा सीटें 36 थी, जो 2011 में बढ़कर 39 हो गईं। गौरतलब है कि 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्र होने के बाद से 1991 तक हिंदुओं की जनसंख्या में 41.89 फीसदी की वृद्धि हुई, जबकि इसी दौरान मुस्लिमों की जनसंख्या में 77.42 फीसदी की बेलगाम वृद्धि दर्ज की गई। इसी तरह 1991 से 2001 के बीच असम में हिंदुओं की जनसंख्या 14.95 प्रतिशत बढ़ी, जबकि मुस्लिमों की 29.3 फीसदी बढ़ी। इस घुसपैठ के कारण असम में जनसंख्यात्मक घनत्व गड़बड़ा गया और सांप्रदायिक दंगों का सिलसिला शुरू हो गया। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा बोडो आदिवासियों ने भुगता।

इन घुसपैठियों को भारतीय नागरिकता देने के काम में असम राज्य कांग्रेस की राष्ट्र विरोधी भूमिका रही है। घुसपैठियों को अपना वोट बैंक बनाने के लिए कांग्रेसियों ने इन्हें बड़ी संख्या में मतदाता पहचान पत्र एवं राशन कार्ड तक हासिल कराए। नागरिकता दिलाने की इसी पहल के चलते घुसपैठिए कांग्रेस को झोली भर–भर के वोट देते रहे हैं। कांग्रेस की तरुण गोगाई सरकार इसी बूते 15 साल सत्ता में रही। लेकिन लगातार घुसपैठ ने कांग्रेस की हालत पतली कर दी थी। फलस्वरूप भाजपा सत्ता में आ गई। इस अवैध घुसपैठ के दुष्प्रभाव पहले अलगाववाद के रूप में देखने में आ रहे थे, लेकिन बाद में राजनीति में प्रभावी हस्तक्षेप के रूप में बदल गए। इन दुष्प्रभावों को पूर्व में सत्तारूढ़ रहा कांग्रेस का केंद्रीय व प्रांतीय नेतृत्व जानबूझकर वोट बैंक बनाए रखने की दृष्टि से अनदेखा करता रहा है। असम को बांग्लादेश से अलग ब्रह्मपुत्र नदी करती है। इस नदी का पाट इतना चौड़ा और दलदली है कि इस पर बाड़ लगाना या दीवार बनाना नामुमकिन है। केवल नावों पर सशस्त्र पहरेदारी के जरिए घुसपैठ को रोका जाता है। लेकिन अब नरेंद्र मोदी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा के घुसपैठियों के विरुद्ध कड़े रुख के चलते अब इनकी वापसी भी षुरू हो गई है।

दरअसल 1971 से ही एक सुनियोजित योजना के तहत पूर्वोत्तर भारत, बंगाल, बिहार और दूसरे प्रांतों में घुसपैठ का सिलसिला जारी है। म्यांमार से आए 60,000 घुसपैठिए रोहिंग्या मुस्लिम भी कश्मीर, बेंगलुरु और हैदराबाद में गलत तरीकों से भारतीय नागरिक बनते जा रहे हैं। जबकि कश्मीर से हिंदू, सिख और बौद्धों को धकिया कर पिछले 3 दशक से शरणार्थी बने रहने को विवश कर दिया है। प्रधानमंत्री राजीव गांधी सरकार ने तत्कालीन असम सरकार के साथ मिलकर फैसला लिया था कि 1971 तक जो भी बांग्लादेशी असम में घुसे हैं, उन्हें नागरिकता दी जाएगी और बाकी को भारत की जमीन से निर्वासित किया जाएगा। इस फैसले के तहत ही अब तक कई बार एनआरसी ने नागरिकों की वैध सूची जारी करने की कोशिश की, लेकिन मुस्लिम वोट–बैंक की राजनीति के चलते कांग्रेस, वामपंथी और तृणमूल एनआरसी का विरोध करते रहे हैं। अतएव 2005 में सर्बानंद सोनोवाल बनाम भारत संघ मामले में असम में अवैध प्रवासियों के पहचान से जुड़े एक पुराने कानून को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि असम में होने वाली भारी घुसपैठ ने राज्यों के नागरिकों के जीवन को आमूलचूल प्रभावित किया है। यह स्थिति एक तरह के अघोशित बाहरी आक्रमण जैसी है।

बांग्लादेश के साथ भारत की कुल 4097 किलोमीटर लंबी सीमा–पट्टी है, जिस पर जरूरत के मुताबिक सुरक्षा के इंतजाम नहीं हैं। इस कारण गरीबी और भुखमरी के मारे बांग्लादेशी असम और बंगाल में घुसे चले आते हैं। क्योंकि यहां इन्हें कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल अपने–अपने वोट बैंक बनाने के लालच में भारतीय नागरिकता का सुगम आधार उपलब्ध करा देते हैं। मतदाता पहचान पत्र जहां इन्हें भारतीय नागरिकता का सम्मान हासिल करा देता है, वहीं राशन कार्ड की उपलब्धता इन्हें बीपीएल के दायरे में होने के कारण मुफ्त अनाज की सुविधा दिला देती हैं। आसानी से बन जाने वाले बहुउद्देशीय पहचान वाले आधार कार्ड भी इन घुसपैठियों ने बड़ी मात्रा में हासिल कर लिए हैं। इन सुविधाओं की आसान उपलब्धता के चलते देश में घुसपैठियों की तादाद चार करोड़ से भी ज्यादा बताई जा रही है। यह अच्छी बात है कि अब इनकी नाक में नकेल डालकर बाहर का रास्ता दिखाने की मुहिम युद्ध स्तर पर चल रही है।

नजरिया

अमेरिका-ईरान युद्ध से महंगाई के कारण आमजन प्रभावित

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

भले ही 1970 के तेल संकट जैसे हालात होने की संभावना ना हो या 2008 जैसी वित्तीय मंदी के हालात ना हो फिर भी एक बात साफ है कि अमेरिका–ईरान के बीच करीब तीन माह से चल रहे युद्ध के नकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। चाहे एशिया के देश हो या फिर योरोपीय देश सभी केवल वैश्विक तनाव ही नहीं अपितु ईंधन आपूर्ति प्रभावित होने से बढ़ते दामों को रोकने में विफल ही हो रहे हैं। पिछले दस–पन्द्रह दिनों में ही हमारे देश में पेट्रोल– एलपीजी–सीएनजी– पीएनजी के दामों में एक बार नहीं अपितु तीन बार बढ़ोतरी हो चुकी है। हांलाकि वर्तमान हालातों में सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। विपक्ष चाहे लाख आरोप लगाये या आंदोलन–प्रदर्शन करें पर अंतरराष्ट्रीय हालातों से आंख नहीं मूंदनी चाहिए। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आमजन से आग्रह को भी इसी संदर्भ में सकारात्मकता से लिया जाना चाहिए। वैसे भी जब संकट का दौर हो और उस संकट के लिए हम या हमारी सरकार जिम्मेदार नहीं हो तो फिर देश में नकारात्मक माहौल बनाने के स्थान पर सकारात्मक माहौल बनाया जाना चाहिए। यह किसी एक व्यक्ति या किसी एक दल का नहीं अपितु सभी राजनीतिक दलों का दायित्व हो जाता है। अमेरिका–ईरान युद्ध के कारण कच्चे तेल और एलपीजी की आपूर्ति बुरी तरह से प्रभावित हुई है। ईंधन संकट का बड़ा कारण अमेरिका–ईरान युद्ध ना होकर अमेरिका–ईरान युद्ध के कारण हार्मुज संकट बन गया है। हार्मुज के रास्ते से ही कच्चे तेल की आपूर्ति होती है और तनाव के चलते हार्मुज जनडमरुमध्य रास्ते को अवरुद्ध कर दिया गया है इससे आपूर्ति प्रभावित हो रही है। यह तो वैकल्पिक उर्जा के रुप में देश में सोलर, विण्ड एनर्जी के क्षेत्र में पिछले सालों में योजनाबद्ध तरीके से तेजी से और बेहतर काम हुआ है और इसी का परिणाम है कि आज प्रधानमंत्री इलेक्ट्रोनिक वाहनों के उपयोग या सोलर एनर्जी के उपयोग पर खुले तौर पर आग्रह करने की स्थिति में है। नवीकरणीय उर्जा के क्षेत्र में देश में तेजी से काम हुआ है और हो रहा है जो एक हद तक संकट को कम करने में सहायक बन रहा है।

इसमें भी कोई दो राय नहीं कि युद्ध में नुकसान अमेरिका को ही अधिक हो रहा है। ईरान तो अपने घर से लड़ रहा है और उसके निशाने पर आसपास के देश है। ऐसे में स्टेक तो अमेरिका-इजरायल का ही हो जाता है। इसके अलावा एक बात और समझनी होगी कि ट्रंप 2 में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आये दिन तुगलकी फरमान जारी कर दुश्मन ही दुश्मन बनाएं है। गली के गुंडे जैसी पहचान बन गई है ट्रंप की तो दूसरी और अमेरिका के ही अधिकांश लोगों का भरोसा ट्रंप ने खो दिया है।

आज की दुनिया आइसोलेट दुनिया नहीं है। एक देश की दूसरे देश पर निर्भरता बढ़ी है। कहीं से ईंधन के लिए तो कहीं से खाद्यान्न, कहीं दवा, कहीं अन्य किसी वस्तु के लिए निर्भरता बढ़ी है। युद्ध के चलते इंटरनेशनल लोजिस्टिक सेवाएं प्रभावित हुई है। जहां तक देश की ही बात की जाएं तो पेट्रोल, डीजल, एलपीजी आदि के कीमत में बढ़ोतरी का व्यापक प्रभाव पड़ने लगा है। सीधी सी बात है जब आवागमन महंगा होगा चाहे वह आम आदमी, सार्वजनिक क्षेत्र या लोजिस्टिक का हो तो उसका सीधा सीधा वस्तुओं और सेवाओं पर पड़ेगा ही। यही कारण है ईंधन यानी तेल के भावों में बढ़ोतरी के साथ ही वस्तुओं और सेवाओं के भाव प्रभावित होने लगे हैं। इसके साथ ही आयात पर निर्भर वस्तुओं के भाव प्रभावित होने लगे हैं। जहां तक तेल का प्रष्न है देश में खाद्य तेल और अखाद्य तेल दोनों ही प्रभावित हो रहे हैं। खाद्य तेलों में भी आयात पर निर्भरता अधिक है। लाख प्रयासों के बावजूद तिलहन मिशन से तिलहनों का उत्पादन तो बढ़ा है पर अभी विदेशी निर्भरता बनी हुई ही है। इसी तरह से अन्य वस्तुओं के भाव प्रभावित होने लगे हैं। जहां तक सेवा क्षेत्र का प्रष्न है स्वीगी–जोमेटो आदि सेवा प्रदाताओं ने पिछले दिनों में अपने दामों में 16 फीसदी से भी अधिक की बढ़ोतरी कर दी है। मोबाइल सेवा प्रदाताओं ने प्लानों को रिवाइज किया हैं तो उबेर–ओला जैसे सेवा प्रदाताओं ने किराया बढ़ा दिया है। हो तो यहां तक रहा हैं कि बैंकों द्वारा जमाओं पर ब्याज दर में कमी लाना शुरु कर दिया है। एक बात साफ हो जानी चाहिए कि लोजिस्टिक लागत बढ़ेगी तो उसका असर सभी वस्तुओं में देखने को मिलेगा। भारत सरकार वेनेजुएला से वैकल्पिक तरीके से कच्चे तेल लाने का प्रयास कर रही है तो अन्य विकल्प भी खोजे जा रहे हैं। पर यह साफ हो जाना चाहिए कि कच्चे तेल की आपूर्ति जब तक सामान्य नहीं हो जाती तब तक पूरी तरह से संकट समाप्त होने की कल्पना नहीं की जा सकती। इन वैश्विक हालातों के पीछे अमेरिका–ईरान की हठधर्मिता ही है। अमेरिका–इजरायल ने ईरान से लड़ाई शुरु करते समय रुस यूक्रेन युद्ध के हालातों से सबक नहीं लिया। रुस के सामने यूक्रेन पिद्दी सा देश होने के बावजूद आज तीन साल से भी अधिक समय होने के बावजूद निर्णायक स्तर पर नहीं पहुंचा है। पर अमेरिका ने यह सोचा था कि दो–तीन दिन में ही ईरान को घुटने टिकवा देंगे और यही अमेरिका की नासमझी रही। मानो या ना मानो पर वास्तविकता यह है कि आज अमेरिका के सामने अपनी प्रतिष्ठा बनाये रखने का संकट आ गया है और यही कारण है कि अंदरखाने अमेरिका और ट्रंप किसी भी तरह से सीज फायर के लिए प्रयासरत है।

इसमें भी कोई दो राय नहीं कि युद्ध में नुकसान अमेरिका को ही अधिक हो रहा है। ईरान तो अपने घर से लड़ रहा है और उसके निशाने पर आसपास के देश है। ऐसे में स्टेक तो अमेरिका–इजरायल का ही हो जाता है। इसके अलावा एक बात और समझनी होगी कि ट्रंप 2 में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आये दिन तुगलकी फरमान जारी कर दुश्मन ही दुश्मन बनाएं है। गली के गुंडे जैसी पहचान बन गई है ट्रंप की तो दूसरी और अमेरिका के ही अधिकांश लोगों का भरोसा ट्रंप ने खो दिया है। ऐसे में सम्मानजनक सीजफायर ही अमेरिका के लिए अब इस संकट से निकलने का रास्ता रह गया है और इसके लिए ही अंदरखाने प्रयास जारी है। (साभार : प्रभा साक्षी)

महत्त्वपूर्ण

Printed& Published by Devendra Sharma on behalf of owners M/s. New Media Company,6/4 , Ist floor, Cantonment station road, Bengaluru-51and printed at Dinasudar Printing Division, 116, Queens Road, Bengaluru-560052. **Editor-Shreekant Parashar**, (*Responsible for selection of news under PRB Act.) Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any suchmanner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.**RNI No. 58061/93. Regn No.: RNP/KA/BGS/2050/2015-2017 posted at Bengaluru PSO Mysore Road Bengaluru-560 026**

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वर्गीकृत, टैंड़र एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी वह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उत्पादों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक या मालिकान को पाठक किसी भी रूप में उत्तरदाई नहीं बना सकता।– **दक्षिण भारत राष्ट्रमत**

जयशंकर ने साइप्रस में यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों से मुलाकात कर साझा हितों पर चर्चा की

निकोसिया/भाषा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बृहस्पतिवार को साइप्रस में यूरोपीय संघ (ईयू) के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की एक अनौपचारिक बैठक में हिस्सा लिया और उभरती बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था में व्यावहारिक सहयोग एवं साझा हितों पर चर्चा की।

जयशंकर पश्चिम एशिया में संघर्ष और अन्य भू-राजनीतिक मुद्दों के बीच लिमासोल में आयोजित बैठक में शामिल होने के लिए बुधवार को साइप्रस पहुंचे। यह बैठक जिम्मिच फोरम के नाम से जानी जाती है।

विदेश मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, यूरोपीय संघ के साथ हमारी साझेदारी कई क्षेत्रों में लगातार गहरी होती जा रही है। हमने उभरती बहुध्रुवीय व्यवस्था में अवसरों, व्यावहारिक सहयोग और हमारे साझा हितों पर चर्चा की।

जयशंकर ने जिम्मिच फोरम से इतर यूरोपीय संघ के विदेश मंत्री और स्पेन सरकार में सहयोग मंत्री जोस मैनुअल अल्बारेस से भी मुलाकात की। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, हमने व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और लोगों से लोगों के संबंधों को बढ़ाने के लिए आगे के कदमों पर चर्चा की। वैश्विक और क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर उनके (जोस मैनुअल) विचारों की सराहना करता हूं।

जिम्मिच फोरम यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक है, जो प्रमुख भू-आर्थिक चुनौतियों, सुरक्षा और रणनीतिक मामलों पर चर्चा करने के लिए समय-समय पर आयोजित की जाती है।

जयशंकर ने जिम्मिच फोरम से इतर नीदरलैंड, पोलैंड, फ्रांस, स्लोवाकिया और एस्टोनिया के विदेश मंत्रियों और पोलैंड के उप प्रधानमंत्री राडोस्लाव सिकोरस्की के साथ भी संक्षिप्त बैठकें कीं।

अभिनेत्री ईशा सिंह और टीवी हस्ती रजत दलाल गुरुवार को मुंबई, महाराष्ट्र में 'ऑब्सेस' की स्क्रीनिंग में शामिल हुए।

मैं खुद को बहुत सीरियसली नहीं लेता : सैफ अली खान

मुंबई/एजेन्सी। अभिनेता सैफ अली खान इन दिनों अपनी अपकमिंग नेटफ्लिक्स की फिल्म 'कर्तव्य' को लेकर चर्चा में हैं। इस बीच प्रमोशन में व्यस्त अभिनेता ने बताया कि मैं खुद को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। आईएएनएस से बातचीत में सैफ अपनी 25 साल पुरानी वायरल लाइन मैं गिटार खेलता हूं पर न केवल प्रतिक्रिया दी बल्कि क्लिप को बेहद मजेदार भी बताया। इंटरव्यू के दौरान जब उनके को-स्टार रसिका दुग्गल और मनीष चौधरी से पूछा गया कि सैफ सेट पर भी वन-लाइनर्स देते हैं या नहीं तो रसिका ने उनकी कॉमिक टाइमिंग की तारीफ करते हुए कहा, हर समय! वह हर समय खूब मस्ती करने वाले एक्टर्स में से हैं। इस पर सैफ ने कहा, मैं खुद को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। एक बार जब सीन ठीक से कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ी मस्ती भी कर सकते हैं।

मुकेश अंबानी ने लगातार छठे साल नहीं लिया कोई वेतन

नई दिल्ली/भाषा। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी ने लगातार छठे वर्ष अपनी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) से कोई वेतन नहीं लिया है। उनके लिए लाभांश ही कमाई का मुख्य जरिया बना हुआ है।

कंपनी की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 69 वर्षीय अंबानी ने वित्त वर्ष 2025-26 में वेतन, भत्ते, सुविधाओं और सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में कोई राशि नहीं ली।

अंबानी ने वित्त वर्ष 2008-09 से 2019-20 तक अपने वार्षिक पारिश्रमिक को 15 करोड़ रुपए पर सीमित रखा था। इसके बाद वित्त वर्ष 2020-21 से उन्होंने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर स्वेच्छा से अपना वेतन छोड़ दिया था। उन्होंने तब यह निर्णय लिया था कि जब तक कंपनी और उसके सभी व्यवसाय अपनी पूर्ण कमाई क्षमता पर वापस नहीं आ जाते, वह वेतन नहीं लेंगे। उन्होंने पूरी तरह स्वैच्छिक रूप से अपने इस फैसले को वित्त वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 और अब 2025-26 में भी जारी रखा है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने वित्त वर्ष 2025-26 में 95,754 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे ज्यादा मुनाफा कमाया और कंपनी का बाजार मूल्य 18.19 लाख करोड़ रुपए रहा।

करीब 100 अरब डॉलर के नेटवर्थ के साथ दुनिया के 21वें सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की कमाई का मुख्य स्रोत लाभांश आय है। रिलायंस में उनकी सीधे तौर पर 1.61 करोड़ शेयर की हिस्सेदारी है, जिससे उन्हें वित्त वर्ष 2024-25 के लिए घोषित छह रुपए प्रति शेयर के लाभांश के आधार पर 9.66 करोड़ रुपए की लाभांश आय हुई।

अंबानी के चचेरे भाई निखिल और हितल मेसवानी का पारिश्रमिक 25-25 करोड़ रुपए पर स्थिर रहा। इसमें वेतन, भत्ते, सेवानिवृत्ति लाभ और मुनाफे पर कमीशन शामिल है।

कार्यकारी निदेशक पी एम एस प्रसाद का पारिश्रमिक वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़कर 20.58 करोड़ रुपए हो गया, जो 2024-25 में 19.96 करोड़ रुपए था।

अंबानी के तीनों बच्चों ईशा, आकाश और अनंत को अक्टूबर, 2023 में निदेशक मंडल में शामिल किया गया था। हालांकि, इसके लिए उन्हें कोई वेतन नहीं मिला। उन्हें केवल बैठक शुल्क और मुनाफे पर कमीशन मिला। आकाश और ईशा को पांच-पांच लाख रुपए बैठक शुल्क और 2.5-2.5 करोड़ रुपए कमीशन मिला।

अंबानी 1977 से रिलायंस के निदेशक मंडल में हैं। जुलाई, 2002 में समूह संस्थापक धीरूभाई अंबानी के निधन के बाद उन्हें कंपनी का चेयरमैन बनाया गया था।

वर्ष 2023 में उन्हें अप्रैल, 2029 तक पांच साल के लिए फिर से रिलायंस का प्रमुख नियुक्त किया गया। इस दौरान भी उन्होंने वेतन नहीं लेने का फैसला किया है।

'ब्लास्ट' में अब्राहम बने नजर आएंगे अर्जुन चिदंबरम

मुंबई/एजेन्सी

फिल्म निर्देशक सुभाष के राज की आने वाली फिल्म 'ब्लास्ट' लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। फिल्म को लेकर अब एक नई जानकारी सामने आई है, जिसने दर्शकों की उत्सुकता को और बढ़ा दिया है। मेकर्स ने खुलासा किया है कि अभिनेता अर्जुन चिदंबरम फिल्म में 'अब्राहम' नाम का किरदार निभाते नजर आएंगे। फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में अर्जुन सरजा, प्रीति मुखुनधन और अभिरामी दिखाई देंगे। अब अर्जुन चिदंबरम के किरदार की जानकारी सामने आने के बाद फैंस फिल्म की कहानी को लेकर और ज्यादा उत्साहित हैं। अभी उनके किरदार के बारे में ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि फिल्म में उनकी भूमिका काफी अहम होने वाली है। फिल्म का निर्माण कर रही एजीएस एंटरटेनमेंट ने एक्स टाइमलाइन पर लिखा, ''ब्लास्ट की दुनिया में अब्राहम से मिलिए।'' इसके साथ फिल्म की रिलीज डेट और पूरी टीम को भी टैग किया गया। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है।जानकारी के मुताबिक, 'ब्लास्ट' 28 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। फिल्म को सेंसर बोर्ड से यू/ए सर्टिफिकेट मिल चुका है। मेकर्स का दावा है कि फिल्म में एक्शन, इमोशन और मनोरंजन का पूरा पैकेज देखने को मिलेगा, जो हर उम्र के दर्शकों को पसंद आएगा। यह फिल्म परिवार के साथ बैठकर देखी जा सकती है। फरवरी में मेकर्स ने घोषणा की थी कि फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है। उस दौरान एजीएस एंटरटेनमेंट ने सोशल मीडिया पर एक खास वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें फिल्म के बीटीएस पल दिखाए गए थे। वीडियो में फिल्म की पूरी टीम शूटिंग खत्म होने की खुशी मनाती नजर आई थी। वीडियो शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा था कि फिल्म अब पूरी तरह तैयार है और हमें बेसब्री से इंतजार है कि दर्शक इसे बड़े पर्दे पर देखें।फिल्म की एक और खास बात इसका संगीत है। मशहूर संगीत निर्देशक रवि बसरूर इस फिल्म के जरिए तमिल सिनेमा में डेब्यू करने जा रहे हैं। रवि बसरूर को खास तौर पर 'केजीएफ' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के दमदार संगीत के लिए जाना जाता है।

'गवर्नर' में आर्थिक संकट की कहानी, ट्रेलर में मनोज बाजपेयी के किरदार ने खींचा लोगों का ध्यान

मुंबई/एजेन्सी

बॉलीवुड अभिनेता मनोज बाजपेयी की आने वाली फिल्म 'गवर्नर' इन दिनों चर्चा में बनी हुई है। मंगलवार को फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया, जिसने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। यह फिल्म भारत के इतिहास के उस कठिन दौर को दिखाती है, जब देश 1990 के दशक में गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। उस समय भारत की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि देश दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया था। ट्रेलर में डर, तनाव और देश को बचाने की कोशिशों को बेहद गंभीर अंदाज में दिखाया गया है। फिल्म के ट्रेलर में दिखाया जाता है कि देश की गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर आम जनता में गुस्सा और बेचैनी है। लोग सरकार और आर्थिक हालात को लेकर चिंतित हैं।

भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि देश को आर्थिक रूप से टूटने से कैसे बचाया जाए। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि सरकार और बड़े अधिकारियों को कुछ कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित बताई जा रही है। कहानी भारत के सबसे बड़े आर्थिक संकटों में से एक पर आधारित है। ट्रेलर में मनोज बाजपेयी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर के किरदार में नजर आएंगे। उनका किरदार देश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को संभालने और भारत को संकट से बाहर निकालने की कोशिश करता दिखाई देगा। ट्रेलर में मनोज बाजपेयी का गंभीर और शांत अंदाज दर्शकों को काफी पंसद आ रहा है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म में मनोज बाजपेयी का किरदार पूर्व आरबीआई गवर्नर एस. वेंकटरमणन से प्रेरित हो सकता है। वह 1991 के आर्थिक संकट के दौरान आरबीआई के गवर्नर थे और उस समय देश को आर्थिक संकट से बाहर निकालने में उनकी अहम भूमिका मानी जाती है। हालांकि, फिल्म के निर्माताओं ने अभी तक आधिकारिक रूप से यह पुष्टि नहीं की है कि कहानी पूरी तरह उन्हीं पर आधारित है।फिल्म को सनशाइन पिक्चर्स प्रस्तुत कर रही है। इसे विपुल अमृतलाल शाह ने प्रोड्यूस किया है, जबकि निर्देशन चिन्मय मंडलेकर ने किया है। फिल्म के सह-निर्माता आशिन ए. शाह हैं। कहानी सुवेंदु भट्टाचार्य, सौरभ भारत, रवि असरानी और विपुल अमृतलाल शाह ने मिलकर लिखी है।फिल्म के संगीत पर भी खास ध्यान दिया गया है। इसके गानों के बोल मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने लिखे हैं, जबकि संगीत अमित त्रिवेदी ने तैयार किया है। ट्रेलर में बैकग्राउंड म्यूजिक भी कहानी के तनाव और गंभीर माहौल को मजबूत बनाता दिखाई देता है। फिल्म 'गर्वनर' 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

पूजा

पश्चिम बंगाल के मंत्री खुदीराम टुडू ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के तारापीठ मंदिर में पूजा-अर्चना की।

नेहा धूपिया ने स्वर्ण मंदिर में टेका माथा

मुंबई/एजेन्सी

बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा धूपिया इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं। इसी सिलसिले में वह पंजाब के अमृतसर पहुंचीं, जहां उन्होंने स्वर्ण मंदिर में माथा टेका। उन्होंने इस यात्रा की कई तस्वीरें और वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए हैं, जिन्हें उनके फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। नेहा धूपिया ने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए, जिसमें सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली तस्वीर स्वर्ण मंदिर की थी। इस तस्वीर में नेहा पवित्र सरोवर के पास खड़ी नजर आ रही है। उन्होंने सिर पर पेस्टल कलर का दुपट्टा ओढ़ रखा है और हाथ जोड़कर श्रद्धा के साथ प्रार्थना करती दिखाई दे रही है। वहीं अन्य तस्वीरों में वह अमृतसर के मशहूर खाने का भी आनंद लेती दिख रही है। एक वीडियो में वह लोकल शॉप पर छोले-भटूरे खाते हुई नजर आ रही है। वीडियो में उनके चेहरे की खुशी साफ बता रही है कि उन्हें पंजाब का यह स्वाद बेहद पसंद आया है। एक दूसरी तस्वीर में वह मजाकिया अंदाज में पोज देती दिख रही है।

इस पोस्ट के साथ नेहा धूपिया ने कैप्शन में लिखा, 'इस यात्रा की हर बात खास रही।' कैप्शन में उन्होंने रेड हार्ट, हाथ जोड़ने और एंजल इमोजी का भी इस्तेमाल किया। यह पहली बार नहीं है जब नेहा किसी धार्मिक जगह पर पहुंची हों। इससे पहले वह वृंदावन गई हैं। वहां उन्होंने सेवा कार्यों में हिस्सा लिया था।

अगर नेहा धूपिया के करियर की बात करें तो उन्होंने साल 2002 में मिस इंडिया का खिताब जीतकर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखा था। इसके बाद उन्होंने फिल्म 'कयामत: सिटी अंडर थ्रेट' से बॉलीवुड में शुरुआत की। आगे चलकर 'जूली', 'क्या कूल हैं हम', 'शूटआउट एट लोखंडवाला', 'सिंह इज किंग', 'चुप चुप के' और 'तुम्हारी सुलु' जैसी फिल्मों में काम करके अपनी अलग पहचान बनाई। फिल्मों के अलावा, नेहा टीवी की दुनिया में भी काफी सक्रिय रही हैं। वह कई रियलिटी शो में जज और होस्ट के रूप में नजर आ चुकी हैं। उनका चर्चित चैट शो 'नो फिल्टर नेहा' भी काफी लोकप्रिय रहा। हाल ही में उन्होंने अपने पति अंगद बेदी के साथ मिलकर कपल-बेस्ड पॉडकास्ट फॉर्मेट लॉन्च किया, जिसमें वे चर्चित सेलिब्रिटी कपल्स से बातचीत करते हैं।

गुरुग्राम स्कूल हत्याकांड पर आधारित किताब की कहानी का इस्तेमाल करेगा 'मैचबॉक्स शॉट्स'

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई। प्रोडक्शन हाउस 'मैचबॉक्स शॉट्स' ने दिग्गज अपराध पत्रकार लीना धनखड़ की किताब 'द गुरुग्राम स्कूल मर्डर' के स्क्रीन अधिकार हासिल कर लिए हैं। यह किताब 2017 में गुरुग्राम के एक स्कूल में सात साल के लड़के की हत्या पर आधारित है। इस प्रोडक्शन हाउस के कर्ताधर्ता फिल्म निर्माता श्रीराम राघवन है। इसके अलावा प्रोडक्शन हाउस ने 'अंधाधुन', 'स्कूप', 'आईसी 814: द कंधार हाईजैक', 'खौफ' जैसी फिल्मों और सीरीज पर काम किया है। मैचबॉक्स शॉट्स के मुताबिक, उक्त किताब का फिल्मांकन करने के लिए पीड़ित के परिवार का समर्थन प्राप्त है। 'द गुरुग्राम स्कूल मर्डर' प्रिंस की हत्या से जुड़ी है, जिसका गला कटा हुआ शव आठ सितंबर, 2017 को गुरुग्राम के एक प्रतिष्ठित स्कूल के शौचालय में मिला था। इस घटना के कारण निजी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर व्यापक आक्रोश पैदा हो गया था।

लीना की यह किताब 2024 में प्रकाशित हुई थी जो इस बात की पड़ताल करती है कि कैसे स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच की शुरुआत में स्कूल बस के एक परिचालक पर हत्या का आरोप लगाया था। इसके बाद केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने उसी स्कूल के एक छात्र को हिरासत में लेकर यह आरोप लगाया था कि उसने परीक्षा को देर में कराने के उद्देश्य से हत्या की थी। मैचबॉक्स शॉट्स की दीक्षा ज्योति राउत्रे, जो इस परियोजना का नेतृत्व कर रही हैं, ने कहा कि यह मामला समकालीन शहरी भारत में युवा बच्चों को आकार देने वाले दबावों के बारे में अंधेरे सच को उजागर करता है।

उन्होंने एक बयान में कहा, इस मामले में जो कुछ हुआ वह हर माता-पिता का सबसे बुरा सपना है... हमारा संकल्प है कि हम इस कहानी को सावधानीपूर्वक शोध और बारीकियों के साथ प्रस्तुत करें, जिसकी यह हकदार है। लीना ने कहा, यह महज एक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि एक परिवार के दर्द और न्याय के लिए सालों लंबे संघर्ष की दास्तां है। वह परिवार हर दिन इस अपूरणीय क्षति के साथ जी रहा है। उसे बिना किसी समझौते के न्याय मिलना ही चाहिए। न्याय के लिए प्रयासरत प्रिंस के पिता ने कहा कि उनके परिवार का एक दिन भी ऐसा नहीं गुजारा जब उन्होंने अपने बच्चे को याद न किया हो। उन्होंने कहा, हमारी लड़ाई बहुत लंबी और पीड़ादायक रही है। यह लड़ाई दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलने तक जारी रहेगी। हम चाहते हैं कि सच्चाई अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे ताकि समाज हमारे दर्द को समझ सके और यह सुनिश्चित हो सके कि दोषियों को कभी बख्शा न जाए। अभी तक इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई है कि यह फिल्म होगी या सीरीज।

एक्टर होना हर बार नई दुनिया में कदम रखने जैसा है : सोनाक्षी सिन्हा

मुंबई/एजेन्सी

बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की हाल ही में रिलीज हुई ओटीटी फिल्म 'सिस्टम' को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसी बीच, फिल्म के प्रमोशन के दौरान उन्होंने अभिनय और अपने किरदार को लेकर आईएएनएस से बात करते हुए कई दिलचस्प बातें साझा कीं। उन्होंने बताया कि एक अभिनेता का काम बाहर से देखने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही मुश्किल होता है। आईएएनएस से बात करते हुए सोनाक्षी सिन्हा ने कहा, ''जब कोई एक्टर किसी नए किरदार को निभाता है, तो वह उसकी पूरी दुनिया में कदम रखता है। हर फिल्म और हर रोल एक अलग जिंदगी की तरह होता है, जिसमें नियम, रिश्ते और परिस्थितियां बिल्कुल नई होती हैं। मुझे अभिनय हमेशा रोमांचक लगता है, क्योंकि हर बार कुछ नया सीखने और महसूस करने का मौका मिलता है।'' सोनाक्षी ने कहा कि किसी भी प्रोफेशन को बाहर से देखकर पूरी तरह समझना मुश्किल होता है। जैसे वकील या डॉक्टर की दुनिया को समझना आसान नहीं होता, वैसे ही फिल्म इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, यह सिर्फ वही लोग जानते हैं जो खुद उस प्रक्रिया का हिस्सा रहे हों। लोग अक्सर सोचते हैं कि फिल्में सिर्फ ग्लैमर और कैमरे तक सीमित होती हैं, लेकिन असल में एक फिल्म के पीछे बहुत सारे लोग, मेहनत और तैयारी होती है, जो मिलकर एक कहानी को आकार देती है।''

फिल्म 'सिस्टम' में सोनाक्षी सिन्हा एक वकील का किरदार निभा रही हैं, जिसका नाम नेहा राजवंश है। उसके पिता रवि राजवंश उन्हें खुद को साबित करने की चुनौती देते हैं और सामने एक शर्त रखते हैं, जिसमें 10 केस जीतने की बात कही जाती है। इस शर्त को पूरा करने के लिए वह हाई-प्रोफाइल केस लड़ती हैं। इस दौरान उसकी मुलाकात अभिनेत्री ज्योतिका के किरदार सारिका रावत से होती है। वह एक स्टेनोग्राफर हैं। फिल्म 'सिस्टम' को पम्मी बावेजा, हरमन बावेजा और स्मिता बालिगा ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। अश्विनी अय्यर तिवारी ने हरमन बावेजा, अरुण सुकुमार और तस्नीम लोखंडवाला के साथ मिलकर इसकी कहानी लिखी है।

संत दर्शन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

बेंगलूरु के टी-दासरहल्ली के जैन महावीर मंडल के सदस्यों ने आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री रविशंकर जी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। सदस्यों ने श्री रविशंकरजी को आर्ट ऑफ़ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस एवं उनके70वें जन्मदिवस की बधाई दी। इस अवसर पर अध्यक्ष सुरेश चावत, उपाध्यक्ष प्रवीण बोहरा, संगठन मंत्री दिलीप पोखरणा, नवीन मेहता, पंकज तातेड़, निखिल चावत, रूपेश महेता आदि उपस्थित थे।

सफलता का अचूक मंत्र है पहले 'ज्ञान' अर्जन करो, फिर 'आचरण' करो : डॉ.समकितमुनि

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। शहर के मल्लेश्वरम स्थानक में आयोजित प्रवचन में डॉ समकितमुनिजी ने जैन आगमों के सबसे महान सूत्र 'पढ़मं नाणं तओ दया' की मार्मिक व्याख्या की। मुनिश्री ने कहा कि किसी भी कार्य को करने का सबसे सही और सटीक तरीका यही है कि सबसे पहले उस विषय का पूर्ण 'ज्ञान' प्राप्त किया जाए और उसके बाद ही उस पर 'अमल' किया जाए।

यदि हम जानकारी के अभाव में, मात्र जल्दबाजी या अज्ञानता में सीधे ही किसी कार्य में कूद पड़ते हैं, तो कई बार उसके परिणाम हमारे सोचे हुए लक्ष्य के बिल्कुल विपरीत और भयंकर होते हैं। उन्होंने कहा कि बिना सत्य को परखे और बिना पूरी जानकारी जुटाए किया गया कोई भी कार्य कभी सफलता की मंजिल तक नहीं पहुँच सकता। अंधकार में तीर चलाने से केवल भटकाव ही हाथ लगता है।ङ्कङ्ककिसी भी कार्य को उसकी पूर्ण सफलता की स्थिति तक पहुँचाने का अद्भुत मार्ग बताते हुए कहा कि केवल इच्छा कर लेने से मंजिल नहीं मिलती। कोई भी कार्य सफलता की सीढ़ी को पार करके अपनी सही मंजिल तक तभी पहुँचता है, जब उसमें निम्नलिखित 'चार' शक्तियों का महासंयोग मिलता है, आत्म-योग्यता यानी सफलता की सबसे पहली शर्त यह है कि 'हमारा' स्वयं का सही होना अत्यंत आवश्यक है। हमारी नीयत, हमारी सोच, हमारा संकल्प और हमारी योग्यता- जब तक यह आधारभूत ढांचा सही नहीं होगा, तब तक कोई भी इमारत खड़ी नहीं हो सकती। सकारात्मक परिवेश यानी संगत ही रंगत लाती है। हमारे सलाहकार, हमारे सहयोगी, हमारे मित्र- इन सबकी 'संगति' का सही और सकारात्मक होना अनिवार्य है। यदि संगति गलत हो गई, तो वह तुम्हारे अच्छे-भले कार्य को भी पतन के मार्ग पर ले जाएगी। श्रेष्ठ संगति से ही सही दिशा मिलती है। ङ्कङ्कमुनिश्री ने कहा कि अथक परिश्रम यानी सफलता कभी बैठे-बिठाए खैरात में नहीं मिलती। हमारा 'पुरुषार्थ' ही वह इंजन है जो सफलता की गाड़ी को आगे खींचता है। सही दिशा में किया गया निरंतर और प्रामाणिक प्रयास ही किसी कार्य को मुकाम तक पहुँचाता है। भाग्य का साथ यानी कर्म-सिद्धांत का रहस्य बताते हुए कहा, जब हमारी योग्यता, संगति और पुरुषार्थ अपनी चरम सीमा पर होते हैं, तब हमें हमारे पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों अर्थात 'पुण्य' का साथ भी आवश्यक होता है। भाग्य का यह सहारा हमारे मार्ग की अदृश्य बाधाओं को दूर कर देता है।ङ्कप्रवचन के निष्कर्ष में मुनिश्री ने संपूर्ण पांडाल को एक स्वर्णिम संदेश देते हुए कहा, याद रखिए, हम, हमारी संगति, हमारा पुरुषार्थ और हमारा भाग्य जब इन चारों का एक साथ, एक ही दिशा में 'सुयोग' होता है, तभी कोई भी कार्य सफलता के सर्वोच्च शिखर को स्पर्श करता है। इनमें से एक भी कड़ी कमजोर पड़ी, तो सफलता दूर खिसक जाती है। ङ्कङ्कइस पावन मौके पर श्रीरामपुरम संघ के कई गणमान्य श्रावकों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और मुनिश्री के दर्शन-वंदन का लाभ लिया। इस मौके पर आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। मल्लेश्वरम संघ के अध्यक्ष प्रकाश बाफना ने आभार ज्ञापन किया और संचालन धर्मीचंद बोहरा ने किया।

सहयोग

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

बेंगलूरु के कांठा प्रांत जैन ट्रस्ट के सदस्यों ने गुरुवार को राजाजीनगर स्थित दीनदयाल डायलेसिस सेंटर में चल रही डायलेसिस योजना के अंतर्गत जरूरतमंद मरीज को आर्थिक राशि प्रदान की गई। ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य अर्थ सहयोग कर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों पर पड़ने वाले इलाज के भारी खर्च को कम करना है।

सऊदी अरब की जेल में 20 साल काटने के बाद केरल लौटा अब्दुल रहीम

कोझिकोड (केरल)/भाषा। सऊदी अरब में मृत्युदंड का सामना कर रहा अब्दुल रहीम खाड़ी देश में करीब दो दशक जेल में बिताने के बाद 'ब्लड मनी' चुकाकर बृहस्पतिवार को अपने गृह राज्य केरल लौट आया। जनसहयोग से जुटाई गई 34 करोड़ रुपए की 'ब्लड मनी' राशि अदा किए जाने के बाद उसे जेल से रिहा किया गया।

करीपुर हवाई अड्डे पर उतरने के बाद रहीम को उनके परिजन बाहर लेकर आए। अपनी मातृभूमि पर कदम रखते ही रहीम की आंखों से आंसू छलक पड़े।

व्यवसायी बॉबी चेम्मनूर हवाई अड्डे पर उनके स्वागत के लिए मौजूद थे। उन्होंने रहीम को देखते ही उसे गले लगा लिया। रहीम ने वहां मौजूद लोगों और मीडिया का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और 'थम्स-अप' का संकेत दिखाकर अपनी खुशी जाहिर की।

उसने संवाददाताओं से कहा, मैं उन सभी लोगों का आभारी हूं जिन्होंने मेरी मदद की। इसके बाद वह घर के लिए रवाना हो गया, जहां उसकी मां करीब 20 वर्षों से बेटे के लौटने का इंतजार कर रही थीं।

रहीम 2006 में नौकरी के लिए सऊदी अरब गया था। घर पर मां के अलावा रिश्तेदार, दोस्त और स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में एकत्र थे। बकरीद के दिन रहीम की वापसी ने लोगों की खुशी और बढ़ा दी। वहां मौजूद लोगों ने कहा, हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है।

घर पहुंचते ही रहीम ने दरवाजे पर अपनी मां को गले लगा लिया और चारों ओर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। इसके बाद वह भीड़ की ओर मुड़ा, हाथ हिलाया लेकिन गला भर आने के कारण कुछ बोल नहीं सका।

विफा के विजयवाड़ा चैप्टर के अध्यक्ष बने ओमप्रकाश काछवाल और महामंत्री बने गजानंद पारीक

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

विजयवाड़ा। विप्र फाउंडेशन (विफा) जोन 16- ए के अंतर्गत विजयवाड़ा चैप्टर की साधारण सभा गत 24 मई को सम्पन्न हुई। बैठक में संयोजक कमल तिवाड़ी ने उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय महामंत्री (दक्षिण) भगवान व्यास, जोन के अध्यक्ष गोपाल शर्मा, चैप्टर के पूर्व अध्यक्ष सतपाल शर्मा को मंच पर आमंत्रित किया। भगवान परशुराम की पूजा के बाद गोपाल शर्मा ने अपने स्वागत भाषण में संगठन का महत्व बताते हुए सभी को एकजुट होकर विप्र फाउंडेशन को मजबूत करने का आह्वान किया।

क्षेत्रीय महामंत्री भगवान व्यास ने विप्र फाउंडेशन की स्थापना से लेकर अभी तक के किए गए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने विप्र फाउंडेशन की नीतियों, उद्देश्यों और संगठन की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से बताया। जोन अध्यक्ष ने वर्ष 2026-28 के लिए मनोनीत पदाधिकारियों के नाम की घोषणा की जिसमें अध्यक्ष ओमप्रकाश काछवाल, उपाध्यक्ष सुनील जोशी व हर्ष व्यास, महामंत्री गजानंद पारीक, सहमंत्री प्रदीप जोशी व गोविंद दाधीच, कोषाध्यक्ष रामनारायण शर्मा एवं कार्यकारणी समिति में किशोर पारीक, राजेश पल्होद, विनोद पारीक, प्रेम तिवाड़ी, सुरेंद्र शर्मा, घनश्याम जोशी के नामों की घोषणा की।विजयवाड़ा चैप्टर के पूर्व अध्यक्ष सतपाल शर्मा एवं नवगठित पदाधिकारियों का सम्मान क्षेत्रीय महामंत्री भगवान व्यास एवं जोन के अध्यक्ष गोपाल शर्मा ने किया।कमल तिवाड़ी ने धन्यवाद दिया।

प्राणी सेवा परमात्मा की भक्ति से बढ़कर : राष्ट्रसंतश्री कमलमुनि

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। शहर के यशवंतपुर जैन स्थानक में उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रसंतश्री कमलमुनिजी कमलेश ने कहा कि किसी भी धर्म ग्रंथ में यह नहीं लिखा है कि असहाय निर्दोष बेकसूर पर जुल्म करने वाला जालिम सजा नहीं पाएगा। खुदा और भगवान के घर पर देर है, अंधेर नहीं। कर्मों के दरबार में कोई बच नहीं पाएगा। वहां पर रिश्वत और जैक कुछ भी चलने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि हम जैसे खेत में बीज डालेंगे, वैसी फसल मिलेगी, जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। किसी को तकलीफ देने से बड़ा और कोई पाप नहीं है और किसी को सुख पहुंचाना उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। मुनि कमलेशजी ने कहा कि अपने गुनाहों पर जिसको पश्चाताप नहीं होता, उसका दान, तीर्थ, सेवा, धाम, आत्म कल्याण में सहयोगी नहीं बन सकता।

भगवान और खुद के चरणों में अहंकार, क्रोध, स्वार्थ, लोभ, मोह और नफरत व्यसन और बुराइयों की कुर्बानी देंगे तभी वह हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे। वस्तु से भगवान का कोई संबंध नहीं है, केवल पवित्र भाव उनके पास में पहुंचते हैं। विश्व का कोई भी महापुरुष किसी भी प्राणी को सताने की इजाजत नहीं देता है। यदि हम किसी से प्यार नहीं कर सकते तो नफरत करने का कोई अधिकार नहीं है। ङ्कङ्कसंघ के अध्यक्ष सुमेरसिंह मुणोत, मंत्री रमेश बोहरा, अन्नराज जैन, उत्तमचंद भलगट कोठारी, नेमीचंद कटारिया, लादूलाल दलाल, किशोर कुमार सिंघवी, बाबूलाल मेहर सहित विहार ग्रुप के अनेक कार्यकर्ताओं ने विहार सेवा का लाभ लिया।

जीतो स्वयं-वी कनेक्ट का कार्यालय दर्शन कार्यक्रम आयोजित

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। शहर के जैन इन्टरनेशनल ट्रेड आर्गेनाइजेशन(जीतो) स्वयं वी कनेक्ट द्वारा जीतो बेंगलूरु नॉर्थ कार्यालय में छठे कार्यकाल के प्रथम कार्यालय दर्शन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का नेतृत्व रेफरल प्रमुख सीए सुखदेवी जैन, रेफरल लीड प्रज्ञा सेठी एवं रेफरल सचिव मोक्षा सोलंकी ने किया। लेडीज विंग नॉर्थ की अध्यक्षा लक्ष्मी बाफना, सहमंत्री मीना बडेरा, सचिव रक्षा छाजेड़ एवं कोषाध्यक्षा तनुजा मेहता की उपस्थिति थी। कार्यालय दर्शन की मेजबानी सुशीला श्रीश्रीमाल द्वारा वी कनेक्ट नेतृत्व टीम एवं कार्यालय दर्शन समन्वयक रंजना डोडिया के मार्गदर्शन में की गई। सत्र के दौरान क्रांटम तरंग एवं समग्र उपचार विषय पर विशेष प्रस्तुति दी गई। इसमें हीलिंग उपकरण की कार्यप्रणाली की जानकारी साझा की गई।

धर्मेन्द्र बागरेचा बने तेयुप हुब्बल्ली के नए अध्यक्ष

हुब्बल्ली/दक्षिण भारत । तेरापंथ युवक परिषद, हुब्बल्ली की साधारण सभा गदग में आयोजित हुई। पूर्व अध्यक्ष हेमल चोपड़ा ने गत वर्ष 2025-26 की पूरी रिपोर्ट पेश की। कोषाध्यक्ष उत्तम जीरावला ने गत वर्ष का पूरा लेखा-जोखा पेश किया। चुनाव प्रभारी के रूप में रमेश चोपड़ा और जितेंद्र पालगोता ने चयन प्रक्रिया बताई। सर्वसहमति से मनोनयन माध्यम से धर्मेन्द्र बागरेचा को नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। संकेत वडेरा ने सबका आभार व्यक्त किया। मंच का संचालन प्रदीप बागरेचा ने किया।

जहां भगवान, गुरु या सदाचारी व्यक्ति का पदार्पण होता है, वहां के दुख नष्ट हो जाते हैं : आचार्यश्री विमलसागरसूरी

सधनूर/दक्षिण भारत। गुरुवार को सिंधनूर के पास गोरेबल स्थित शरणबसवेश्वर मठ में श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों को संबोधित करते हुए आचार्यश्री विमलसागरसूरीश्वरजी ने कहा कि जहां भगवान, गुरु या सदाचारी व्यक्ति का पदार्पण होता है, वहां के दुख नष्ट हो जाते हैं। पवित्र आत्माओं के आगमन और पूजा-अनुष्ठान से परिसर का वातावरण परिशुद्ध बनता है। वहां के परमाणु सकारात्मक और ऊर्जावान बन जाते हैं। यह पूर्ण मनोवैज्ञानिक तथ्य है। भारतीय समाज हजारों वर्षों से ऐसे पूजा-अनुष्ठान, मंत्रविधान और प्रार्थनाओं के द्वारा सुख-शांति की कामना करता आया है। अब आधुनिक विज्ञान इस तथ्य पर बहुत अनुसंधान कर रहा है। आचार्यश्री ने कहा कि मनुष्य हमेशा अपनी और अपने परिवार की सुख-शांति व समृद्धि चाहता है, इसलिए वह अपने नूतन गृह या व्यापारिक प्रतिष्ठान के शुभारंभ के समय विशेष पूजा-अनुष्ठान करता है। जैन व वैदिक परंपरा को शुभ-मंगल की कामनाओं के साथ ऐसे अनेक विधि-विधान विरासत में मिले हैं। वास्तुपूजा जैन परंपरा का ऐसा ही मंगलमय अनुष्ठान है। यह परिवार की सुख-शांति, समृद्धि और धर्म-अध्यात्म की उन्नति की भावभरी प्रार्थना है। तीर्थंकर प्रतिमा पर जलाभिषेक और पुष्पांजलि से स्नात्र विधान प्रारंभ होता है। आरती, मंगल दीपक के बाद शांतिपाठ के साथ शांतिकलश किया जाता है। इस प्रकार वास्तुपूजा संपन्न होती है। यह गुजरात के पटेल किसान परिवार में जन्मे प्रसिद्ध योगसाधक आचार्य बुद्धिसागरसूरीश्वरजी की भावपूर्ण रचना है। देश-विदेश में सभी जैन परिवार इसी वास्तुपूजा से उपासना करते हैं।

अन्नाद्रमुक के पूर्व मंत्री विजयभास्कर जल्द ही अपने 'राजनीतिक कदम' की घोषणा करेंगे

पुडुकोट्टई (तमिलनाडु)/भाषा। 'ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम' (अन्नाद्रमुक) के पूर्व मंत्री सी. विजयभास्कर ने बृहस्पतिवार को अपने समर्थकों के साथ परामर्श बैठक करके सबको चौंका दिया। विजयभास्कर उन बागी विधायकों में शामिल थे, जो पार्टी में लौट आए। बाद में, उन्होंने घोषणा की कि उनका अगला राजनीतिक कदम उनके समर्थकों और उन्हें विरालीमलाई विधानसभा क्षेत्र से चुनने वाले लोगों की इच्छाओं के अनुरूप होगा। उन्होंने यह भी कहा कि वह जल्द ही अपने अगले कदम की घोषणा करेंगे।

पेशे से चिकित्सक विजयभास्कर ने कहा कि उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों से प्रतिक्रिया (फीडबैक) प्राप्त की है, जिनकी वजह से उन्हें 23 अप्रैल को हुए विधानसभा चुनाव में विरालीमलाई से जीत हासिल हुई है। उन्होंने यहां पत्रकारों से कहा, मैंने धैर्यपूर्वक उनकी बातें सुनीं। मैंने उनसे धैर्य रखने को कहा। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह अपने समर्थकों के साथ सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) में शामिल होने की योजना बना रहे हैं, तो विजयभास्कर ने जवाब दिया, मैं अटकलों का जवाब नहीं दे सकता।

विजयन से जुड़ी ईडी की छापेमारी उन्हें माकपा की आलोचना से बचाने के लिए की गई: केरल के मंत्री

तिरुवनंतपुरम/भाषा। केरल सरकार में मंत्री के. मुरलीधरन ने बृहस्पतिवार को कहा कि कांग्रेस को संदेह है कि पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से जुड़े आवासों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी का मकसद उन्हें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के भीतर हो रही उनकी कड़ी आलोचना का सामना करने से बचाना था।

मुरलीधरन ने दोहराया कि कांग्रेस न तो ईडी का समर्थन करती है और न ही एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी का। उन्होंने दावा किया कि ऐसी कार्रवाई विजयन के मुख्यमंत्री रहते हुए ही शुरू कर देनी चाहिए थी। मंत्री ने हालांकि राज्य की राजधानी में पूर्व मुख्यमंत्री के किराए के आवास पर छापेमारी के लिए पहुंचे ईडी अधिकारियों के वाहनों पर माकपा कार्यकर्ताओं के कथित हमले की निंदा की।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

शोभायात्रा

बेंगलूरु के पार्श्व सुशीलधाम में गुरुवार को आचार्यश्री अरिहंतसागर सूरीश्वरजी की निश्रा में आयोजित उपधान तप के समापन के उपलक्ष्य में उपधान आराधकों के सम्मान स्वरूप शोभायात्रा व वरघोड़े का आयोजन किया गया, जिसमें 9 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक के आराधक जुड़े जिन्होंने 47 दिवसीय तप गुरुकुलवास में रहकर उपधान तप पूर्ण किया।

Printed& Published by Devendra Sharma on behalf of owners M/s. New Media Company, 6/4 , Ist floor, Cantonment station road, Bengaluru-51 and printed at Dinasudar Printing Division, 116, Queens Road, Bengaluru-560052. **Editor-Shreekant Parashar**, (*Responsible for selection of news under PRB Act.) Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any such manner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.
HEAD OFFICE : DAKSHIN BHARAT RASHTRAMAT, New Media Company, 6/4, Cantonment Station Road, Bangalore 560051. Editorial : 080-25363030 / 9945488003. For Advertisement : 9945488002 - email : news@dakshinbharat.com/**RNI No. 58061/93.**